A Daily News Magazine
भोपाल
शुक्रवार, 16 जनवरी, 2026

सुबह सवेरे

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 136, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

प्रसंगवश

पूरी तरह अज्ञात इलाके में भारत के अधिकार पर चीन का अतिक्रमण

दिलनवाज़ पाशा

चीन ने सोमवार को शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावे को दोहराते हुए कहा है कि इस घाटी में चीन की बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी तरह वैध हैं। भारत की आपत्तियों को ख़ारिज करते हुए चीन ने कहा है कि इस घाटी को लेकर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता है। भारत ने 9 जनवरी को इस क्षेत्र में चल रहे चीन के निर्माण की आलोचना करते हुए कहा था कि यह भारतीय क्षेत्र है और भारत के पास अपने हितों की रक्षा के लिए आवश्यक क़दम उठाने का अधिकार है।

पाकिस्तान ने शक्सगाम घाटी क्षेत्र का 5180 वर्ग किलोमीटर हिस्सा एक समझौते के तहत साल 1963 में चीन को सौंप दिया था। पाकिस्तान और चीन के बीच इस क्षेत्र को लेकर हुए समझौते को भारत अवैध मानता हैं। भारत के सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने मंगलवार को दिए एक बयान में कहा है कि जहां तक शक्सगाम घाटी का सवाल है, भारत 1963 में पाकिस्तान और चीन के बीच हुए समझौते को अवैध मानता है।

भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने 9 जनवरी को जारी एक बयान में कहा, 'शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है। हमने कभी भी 1963 के तथाकथित चीन-पाकिस्तान सीमा समझौते को मान्यता नहीं दी है। यह समझौता अवैध और अमान्य है, और भारत इसे पूरी तरह अस्वीकार करता है।'

वहीं, बीजिंग में जब पत्रकारों ने भारत के विदेश मंत्रालय के इस बयान के संबंध में चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि जिस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं वह चीन का हिस्सा है।

उन्होंने कहा, 'अपने ही क्षेत्र में बुनियादी ढांचा निर्माण करना चीन का पूरी तरह से जायज़ अधिकार है। 1960 के दशक में चीन और पाकिस्तान ने एक सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और दोनों देशों के बीच सीमा का निर्धारण किया गया था, जो संप्रभु देशों के रूप में चीन और पाकिस्तान का अधिकार है,' वहीं सीपीईसी को लेकर भारत की आलोचना पर चीन की प्रवक्ता माओ ने चीन का इसे लेकर पहले से चला आ रहा रुख ही दोहराया। उन्होंने कहा कि यह एक आर्थिक सहयोग पहल है, जिसका उद्देश्य स्थानीय सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और लोगों की आजीविका में सुधार करना है। उन्होंने कहा, 'चीन-पाकिस्तान सीमा समझौता और सीपीईसी, कश्मीर मुद्दे पर चीन की स्थिति को प्रभावित नहीं करते और इस पर चीन का रुख पहले जैसा ही बना हुआ है।'

शक्सगाम घाटी कहां है?

शक्सगाम घाटी लद्दाख के उत्तर-पूर्वी हिस्से में स्थित एक रणनीतिक क्षेत्र है। यह इलाका सियाचिन ग्लेशियर के उत्तर, काराकोरम पर्वतमाला के पास पड़ता है।भारत के दावे के मुताबिक यह इलाक़ा जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का अभिन्न हिस्सा है और इस पर भारत का अधिकार है। भारत के अधिकारिक नक़्शे में यह इलाक़ा सबसे ऊपरी छोर पर है। शक्सगाम घाटी के भौगोलिक और ऐतिहासिक स्वरूप को लेकर ब्रिटिश भूगोलवेत्ता और सर्वे ऑफ़ इंडिया के अधिकारी कैनेथ मेसन का विवरण आज भी अहम माना जाता है।

1926 में प्रकाशित अपनी प्रसिद्ध रिपोर्ट 'शक्सगाम घाटी और आग़िल पर्वत श्रेणियों की खोज और सर्वेक्षण' में मेसन लिखते हैं कि शक्सगाम घाटी और इसकी ऊपरी सहायक घाटियाँ इस सीमा क्षेत्र का 'आखिरी पूरी तरह अज्ञात इलाक़ा' थीं, जहाँ लंबे समय तक किसी बाहरी शक्ति की स्थायी मौजूदगी नहीं रही। मेसन के अनुसार यह क्षेत्र 'मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की जल प्रणालियों के बीच एक महान विभाजक' है, जहाँ से नदियाँ उत्तर में यारकंद की ओर और दक्षिण में सिंधु की ओर बहती हैं।

अपनी इस लगभग सौ साल पुरानी किताब में वे यह भी रेखांकित करते हैं कि शक्सगाम जैसे दुर्गम भूभाग में स्थायी मानव बसावट लगभग असंभव रही है और यदि मनुष्य यहाँ पहुँचा भी है तो वह केवल एक राहगीर या घुमंतू के रूप में।

इतिहास के लंबे दौर में भले ही ये इलाक़ा दुर्गम और वीरान रहा है लेकिन आज यह निर्जन पर्वतीय क्षेत्र रणनीतिक रूप से बेहद अहम है। ब्रितानी भूगोलवेत्ता कैनेथ मेसन इसे मध्य एशिया और भारतीय उपमहाद्वीप की जल प्रणालियों के बीच स्थित एक महान प्राकृतिक जल विभाजक बता चुके हैं। यहां से नदियां एक तरफ़ यारकंद और दूसरी तरफ़ सिंधू घाटी की तरफ़ बहती हैं। आज यही भौगोलिक स्थिति शक्सगाम घाटी को रणनीतिक रूप से संवेदनशील बनाती है क्योंकि यहां बुनियादी ढांचे का विकास न केवल सीमाओं की भौतिक पकड़ मज़बूत करता है, बल्कि सियाचिन, काराकोरम और शिनजियांग क्षेत्र के बीच सैन्य और लॉजिस्टिक पहुंच को भी प्रभावित करता है। यही वजह है कि भारत इसे अपनी संप्रभुता से जुड़ा सवाल मानता है, जबकि चीन इसे अपने नियंत्रण वाले इलाके में वैध गतिविधि बताता है।

शक्सगाम घाटी को लेकर विवाद क्यों है?

भारत का कहना है कि 1963 में पाकिस्तान ने अवैध रूप से लगभग 5,180 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र चीन को सौंप दिया था। भारत का तर्क है कि यह इलाका उस समय भी पाकिस्तान के अवैध कब्ज़े में था, इसलिए भारत ने इस समझौते को गैरक़ानूनी और अमान्य बताया है। भारत इस समूचे क्षेत्र पर अपना दावा करता है जबकि चीन का दावा है कि पाकिस्तान के साथ समझौते के बाद इस इलाक़े पर उसका अधिकार है।

फिलहाल शक्सगाम घाटी क्षेत्र पर चीन का नियंत्रण है और चीन यहां कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर काम कर रहा है। ट्रांस कारोकरम ट्रेक्ट कहे जाने वाले इस इलाक़े का सामान्य प्रशासन भी चीन के हाथ में ही है। चीन इसे शिनजियांग वीगर स्वायत्त क्षेत्र का हिस्सा मानकर प्रशासित करता है। ट्रांस-काराकोरम ट्रेक्ट वह इलाक़ा है जिसे पाकिस्तान ने 1963 में चीन को सौंपा था। हालिया रिपोर्टों के मुताबिक़, चीन इस क्षेत्र में नई सड़कें, सुरक्षा चौकियां और चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के तहत ढांचागत निर्माण कर रहा है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित रिपोर्ट के संपादित अंश)

25 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर निकले

नई दिल्ली (एजेंसी)। पीएम नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को संसद परिसर में 28वें कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेस का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा कि आज

पीएम बोले-

- आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था
- 28वें सीएसपीओसी का उद्घाटन

भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पिछले कुछ सालों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकले हैं। पीएम मोदी ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत में एआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। दुनिया का नंबर-2 स्टील प्रोड्यूसर है। दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। दुनिया का

चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। दुनिया का तीसरा बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संभाल रहे हैं। इसमें कॉमनवेल्थ के 42 देशों से 61 स्पीकर्स और प्रेसाइडिंग ऑफीसर्स शामिल हो रहे हैं। सम्मेलन 14 से 16 जनवरी यानी तीन दिनों तक चलेगा। भारत में लोकतंत्र की पहचान है कि वह आखिरी व्यक्ति तक फायदे पहुंचे। हम लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव से काम कर रहे हैं।

भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत में बदल दिया है

जब भारत आजाद हुआ तब उस दौर में आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी विविधता में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा लेकिन भारत ने विविधता को अपने लोकतंत्र की ताकत में बदल दिया है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब पूरी दुनिया संकट का सामना कर रही थी, भारत भी कई चुनौतियों का सामना कर रहा था। इसके बावजूद उन कठिन परिस्थितियों में भी भारत ने 150 से अधिक देशों को दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराई। यह हमारे सिद्धांत को दर्शाता है- 'पहले लोग, पहले मानवता।' आप जिस स्थान पर बैठे हैं, वह भारत के लोकतांत्रिक सफर का महत्वपूर्ण स्थल है। स्वतंत्रता के अंतिम सालों में इसी सेंट्रल हॉल में संविधान सभा की बैठकें हुई थीं। स्वतंत्रता के बाद 75 साल तक यह भारत की संसद रही। देश के भविष्य से जुड़े कई निर्णय इसी हॉल में लिए गए।

हैदराबाद के मंदिर में तोड़फोड़ के बाद जमकर मचा बवाल

हैदराबाद (एजेंसी)। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से बड़ी खबर सामने आई है। यहां हैदराबाद के पुरानापुल दरवाजे पर देर रात उस समय तनाव का माहौल छा गया जब अज्ञात लोगों ने एक मंदिर में तोड़फोड़ की। अज्ञात लोगों के मंदिर में तोड़फोड़ की खबर फैली तो स्थानीय लोगों में चिंता फैल गई और घटनास्थल के पास भीड़ जमा हो गई। गुस्साए लोगों ने इलाके में जमकर हंगामा किया। पथराव हुआ और कई वाहनों को आग लगा दी गई। इस हिंसा में दस से

ज्यादा पुलिसवाले घायल हुए हैं। पुलिस ने बताया कि तोड़फोड़ की घटना देर शाम को देखी गई, जिसके बाद अधिकारियों को सूचित किया गया।

एआई कॉन्फ्रेंस में सीएम ने बताए बुद्धि के तीन प्रकार, कहा-

यंत्र, मंत्र, तंत्र में दुनिया उलझी, इन पर षड्यंत्र भारी है

भोपाल। राजधानी भोपाल के होटल ताज में आयोजित रीजनल AI इंपैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारतीय परंपरा, दर्शन और आधुनिक तकनीक को जोड़ते हुए कहा कि दुनिया आज मंत्र, यंत्र और तंत्र में उलझी है, लेकिन इन सबसे भारी एक और तंत्र है-षड्यंत्र। उन्होंने चेताया कि AI और तकनीकी प्रगति के बीच इतना सूक्ष्म अंतर करना होगा कि विकास की दौड़ में मानव की मूल प्रकृति नष्ट न हो। मुख्यमंत्री ने तिरुपति बालाजी दर्शन की लंबी कतार का किस्सा सुनाते हुए कहा कि एक नवदंपति में पति 'गोविंदा-गोविंदा' बोल रहा था, जबकि पत्नी कह रही थी-'आगे वाला बोले वही सही है।' कारण बताते हुए सीएम ने मुस्कराकर कहा-'हमारे यहां पत्नी पति का नाम नहीं लेती, पति का नाम गोविंदा था।' इसी से जोड़ते हुए उन्होंने मंच पर पहले हुए प्रभावी भाषणों का जिक्र किया और कहा-'मुझे भी लग रहा है कि आगे वाला जो बोले वही सही है।'

मध्य प्रदेश ज्ञान और साधना की भूमि है- मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश ज्ञान और साधना की भूमि है। भगवान कृष्ण के ज्ञानार्जन का केंद्र सांदीपनि आश्रम यहीं है और शंकराचार्य जी का ध्यान-केंद्र ओंकारेश्वर भी मप्र में स्थित है। उन्होंने कहा, 'अगर हम बुद्धि और विवेक में अंतर करने लगें तो AI और ऐप को भी पसीना आ जाएगा। डॉ. यादव ने स्पष्ट किया कि संसाधनों के बल पर जो बेहतर हो सकता है, वह जनकल्याण के उदाहरणों से सामने आता है। उन्होंने कहा कि AI का उपयोग जनकल्याणकारी योजनाओं और सभी विभागों में किया जाना चाहिए—केंद्र और राज्य, दोनों स्तरों पर AI के उदाहरण देते हुए उन्होंने भगवान गणेश की कथा का उल्लेख किया—पृथ्वी की परिक्रमा को माता-पिता की परिक्रमा से जोड़ना, भारतीय बुद्धिमत्ता का प्रतीक है।

बुद्धि के तीन प्रकार और 'षड्यंत्र' का दौर- सीएम ने बुद्धि के तीन प्रकार गिनाए-मांत्रिक बुद्धि, यांत्रिक बुद्धि और तांत्रिक बुद्धि। उन्होंने कहा कि आज दुनिया मंत्र-यंत्र-तंत्र में उलझी है, लेकिन इन सबसे भारी एक और तंत्र है-षड्यंत्र। मौजूदा दौर में भावनात्मक, रचनात्मक और प्रतिक्रियात्मक हर तरह की व्यवस्थाओं में बारीक अंतर करने की जरूरत है, ताकि प्रगति की दौड़ में हमारी मूल प्रकृति नष्ट न हो।

एआई से नौकरियां नहीं जाएंगी, रोल बदलेंगे- मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कहा कि विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के लिए AI जरूरी है। AI से एफिशिएंसी और ग्रोथ बढ़ेगी। कंप्यूटर आने पर भी नौकरियां जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि असली चुनौती स्किलिंग और रिस्किलिंग की है। नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक 49 करोड़ श्रमिकों पर विशेष ध्यान देना होगा। टियर-2 और टियर-3 शहरों तथा पिछड़े राज्यों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज्यादा बनने चाहिए। अनुराग जैन ने कहा कि वेस्टर्न मॉडल भारतीय समस्याएं नहीं समझ सकते।

एआई नीति, मिशन और सेक्टरल संभावनाएं

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश AI नीति लाने जा रहा है और AI मिशन पर भी काम करेगा। उन्होंने बताया कि स्पेसटेक पॉलिसी हाल ही में लाई गई है। माइनिंग और हेल्थ सेक्टर में AI की बड़ी संभावनाएं हैं। उन्होंने कहा, 'नौ करोड़ आबादी वाले राज्य में अपार संभावनाएं हैं।' मप्र संभावनाओं से भरा राज्य है और आप सबकी मदद से हम आगे बढ़ रहे हैं। सम्मेलन में बताया गया कि MP SEDC WHO स्टैंडर्ड के साथ AI की मदद से अगले तीन महीनों में कुपोषित होने वाले बच्चों का आकलन करेगा। साथ ही वेक्टर बॉर्न डिजीज के संभावित आउटब्रेक का पूर्वानुमान भी लगाया जाएगा। कृषि क्षेत्र में फसल, मौसम और उत्पादन बढ़ाने के लिए भी AI का उपयोग हो रहा है।

शरद की सुबह

ख्वाहिशें जीने और मरने नहीं देती,
अंदरूनी आग को बुझने नहीं देती।
ख्वाहिशें ख़ुशी व ग़म की जननी हैं,
आशा के दीए को बुझने नहीं देती।
हर पल भूतनी-सी पीछे पड़ी रहती,
कभी चैन से सोने-जगने नहीं देती।
मोह-पाश में कसकर बाँधे रहती हैं,
मनुज को ऊपर को उठने नहीं देती।
हजारों बार उठने-गिरने के बावजूद,
पराजय पीछे को हटने नहीं देती।

- रामेश्वरम तिवारी

भारतीय सेना का रॉकेट-मिसाइल फोर्स बनाने पर जोर

- जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा-ईरान बन सकता है नजीर
- जनरल ने कहा-इससे अमेरिका-इजरायल भी कांपते हैं!

नई दिल्ली (एजेंसी)। अभी दुनिया भर में जितने भी संघर्ष हो रहे हैं, उसने एक बात तो साफ कर दिया है कि अब परंपरागत युद्ध के दिन बीत चुके हैं। आज बात सिर्फ मॉडर्न वॉरफेयर, नॉन-कॉन्टैक्ट वॉरफेयर की हो रही है। भारत तो खुद ही ऑपरेशन सिंदूर में इसे आजमा चुका है, जिसके आगे पाकिस्तान के अमेरिकी और चीनी हथियार घुटने टेक चुके हैं लेकिन, भारतीय सेना इतने भर से संतुष्ट नहीं है। हम पूरे साल दो मोर्चों पर अपने चीन-पाकिस्तान जैसे दुश्मन पड़ोसियों के खतरे का सामना करते हैं। इसी को देखते हुए, भारत रॉकेट-मिसाइल फोर्स गठित करने की सोच रहा है। क्योंकि, इस मामले में चीन हमसे बहुत आगे है तो पाकिस्तान ने भी ऐसी मिलिट्री यूनिट बना ली है।

रॉकेट-मिसाइल फोर्स समय की जरूरत- भारत 15 जनवरी, 2026 को हर साल की तरह सेना दिवस मना रहा है। इसी मौके पर हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में भारतीय सेना के प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने भी इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा आवश्यकताएं ऐसी स्पेशलाइज्ड मिलिट्री यूनिट की ओर देखने को कह रही हैं, जिसमें एक कमांड के भीतर लंबी दूरी के रॉकेट और मिसाइल तैनात हों। उन्होंने कहा, हम एक रॉकेट-मिसाइल फोर्स की ओर देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने एक रॉकेट फोर्स गठित कर लिया है और चीन ने भी ऐसी फोर्स बना ली है। यह समय की जरूरत है।

भारत में कई तरह के मिसाइल और रॉकेट- इस समय भारतीय सशस्त्र सेना के पास

स्वदेशी और साझा तौर पर विकसित कई तरह की मिसाइलों की बड़ी खेप है। इसमें अग्नि, ब्रह्मोस, पृथ्वी, प्रलय जैसी मिसाइलें शामिल हैं। कुछ ही दिन पहले भारत ने 120 किमी की अधिकतम रेंज वाले पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट का भी परीक्षण किया है।

- **अभी अलग-अलग यूनिट संभालते हैं-** अभी भारत के मिसाइल और रॉकेट भंडार को आर्मी एयर डिफेंस कोर (८ष्ठ) और आर्टिलरी रेजिमेंट संभालते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से भारत ने अपनी लंबी-दूरी की मारक क्षमताओं को बढ़ाने की कोशिशों पर पूरा जोर दे रखा है। आर्मी चीफ का कहना है कि नए जमाने के जंग में रॉकेट और मिसाइल एक-दूसरे पर निर्भर हो गए हैं। उनका कहना है, %आज आप देखेंगे कि रॉकेट और मिसाइलें आपस में एक-दूसरे से जुड़ गए हैं, अगर हम कोई असर डालना चाहते हैं, तो रॉकेट और मिसाइल दोनों ही ऐसा कर सकते हैं।% वैसे दोनों अलग-अलग हैं और रॉकेट के उलट मिसाइल तय टारगेट को हिट करने के लिए बनाई गई है, जिसमें इंटर्नल गाइडेंस सिस्टम भी होते हैं।

चीन, पाकिस्तान के पास अलग मिसाइल यूनिट

आज की तारीख में चीन और पाकिस्तान दोनों के पास अलग से रॉकेट-मिसाइल मिलिट्री यूनिट हैं। मसलन, चीन ने इसके लिए पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी रॉकेट फोर्स बना रखा है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह से पिटने के बाद पाकिस्तान ने भी चीन की तर्ज पर आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बना ली है। अमेरिकी पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन के पीएलएआरएफ के पास 1,250 से ज्यादा बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें हैं। यही नहीं, उसके पास 600 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड भी हैं, जो 2030 तक 1,000 से ज्यादा तक पहुंच सकते हैं। हालांकि, पाकिस्तान के पास भारत से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड हो सकते हैं, लेकिन बाकी मिसाइलों और रॉकेट के मामले में उसके हाथ काफी तंग हैं। जबकि, चीन की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे है।

ईरान के पास ताकतवर रॉकेट-मिसाइल फोर्स

भारत रॉकेट-मिसाइल फोर्स बनाना चाहता है तो उसे ईरान से सीखने के लिए बहुत कुछ मिल सकता है। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर एयरोस्पेस फोर्स इसके अत्याधुनिक मिसाइलों के भंडारन और संचालन की जिम्मेदारी संभालती है, जो उसके एयरफोर्स के समानांतर काम करती है। ईरान की मिसाइल यूनिट के पास बैल्स्टिक, हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों का बड़ा जखीरा है। यह यूनिट लड़ाकू ड्रोन का संचालन भी देखती है और सीधे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को रिपोर्ट करती है। ईरान की एयरोस्पेस फोर्स की क्षमता पर दुनिया ने तब ज्यादा गौर किया, जब पिछले साल इजरायल के साथ कुछ समय के लिए इसकी लड़ाई शुरू हो गई। इस यूनिट की मिसाइलों ने इजरायल के ताकतवर आयरन डोम को भी नाकाम कर दिया और करीब 25 लोगों की जान चली गई। ईरान के रॉकेट फोर्स की सबसे बड़ी ताकत इसे अंडरग्राउंड सुरंगों में छिपाकर रखना है, जिसका एक विशाल नेटवर्ग बना हुआ है। ईरान की मिसाइलें इन्हीं सुरंगों में रखी गई हैं।

भोपाल का तापमान
अधिकतम 20 °c
न्यूनतम 18°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ शुक्रवार, 16 जनवरी 2026

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

जम्मू-कश्मीर को दो अलग राज्य बनाने की मांग

● सज्जाद लोन बोले-सौहार्द्रपूर्ण अलगाव पर विचार का समय

श्रीनगर (एजेंसी)। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने जम्मू और कश्मीर को दो अलग राज्यों में बांटने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब दोनों क्षेत्रों के बीच सौहार्द्रपूर्ण अलगाव पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। लोन ने कहा कि कश्मीर ऐसे क्षेत्रीय रवैये को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जो लगातार कश्मीरियों को बदनाम करता रहा। देश के बाकी हिस्सों में यह धारणा फैलाए कि जम्मू देश के साथ है और कश्मीर आतंकवाद का क्षेत्र है। जम्मू-कश्मीर के

पूर्व मंत्री सज्जाद लोन ने यह बातें बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहीं। कुछ दिन पहले भाजपा के जम्मू नॉर्थ से विधायक श्याम लाल शर्मा ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि जम्मू अब कश्मीर का बोझ नहीं उठा सकता। लोन ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से कश्मीर के बडगाम में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने का चुनावी वादा पूरा करने की मांग की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा यही है कि किए गए वादे को निभाया जाए और यूनिवर्सिटी बडगाम में ही रहे।

एक्टर विजय को सुप्रीम कोर्ट से लगा बड़ा झटका

फिल्म 'जन नायकन' को लेकर दिया हाईकोर्ट जाने का आदेश

नई दिल्ली (एजेंसी)। अभिनेता से नेता बने विजय अपनी आखिरी फिल्म जन नायकन को लेकर चर्चा में हैं। मद्रास हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद फिल्म के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मगर, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए मेकर्स को हाईकोर्ट जाने का आदेश दिया है। जन नायकन के मेकर्स ने सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई मद्रास हाईकोर्ट में ही जारी रखने का आदेश दिया है। ये

फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होनी थी, लेकिन केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड से मंजूरी न मिलने के कारण फिल्म की रिलीजिंग आगे बढ़ा दी गई है। फिल्म के मेकर्स की याचिका खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट 20 जनवरी को मामले पर सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकार लगाते हुए कहा, हम इस मामले पर सुनवाई करने के इच्छुक नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में मेकर्स का पक्ष रखते हुए एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने कहा , फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी। हमें पूरे भारत में 5000 थियेटर्स मिले थे।

अमेरिका की धमकी के बाद शिया देश का सरेंडर

● पीछे हटा ईरान, विदेश मंत्री बोले-कोई फांसी नहीं ● ट्रम्प का दावा-प्रदर्शनकारियों की हत्याएं अब रुकीं

वॉशिंगटन (एजेंसी)। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की धमकियों के बाद ईरान प्रदर्शनकारियों को फांसी देने के फैसले से पीछे हट गया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बुधवार को कहा कि ईरान की ओर से लोगों को फांसी देने की कोई योजना नहीं है। विदेश मंत्री ने फॉक्स न्यूज के स्पेशल रिपोर्ट विद ब्रेट बेयर कार्यक्रम में दिए एक इंटरव्यू में कहा, फांसी देने की कोई योजना नहीं है। फांसी का तो सवाल ही नहीं उठता। वहीं, बुधवार को ट्रम्प ने भी बताया कि ईरान में प्रदर्शनकारियों की हत्याएं रुक गई हैं। इससे पहले ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर तेज ट्रायल और जल्दी से

फांसी देने का ऐलान किया था। ईरान बुधवार को 26 साल के प्रदर्शनकारी इरफान सुलतानी को फांसी देने वाला था। इस फैसले के बाद ट्रम्प ने ईरान को कड़ा जवाब देने की धमकी दी थी। ट्रम्प ने कहा ,अगर वे फांसी देते हैं, तो आप कुछ भयानक देखेंगे। ईरान ने सरकारी टीवी चैनल पर राष्ट्रपति ट्रम्प को जान से मारने की धमकी जारी की थी। रिपोर्ट के मुताबिक धमकी पर्शियन में थी। इस धमकी में पेंसिल्वेनिया के बटलर में 2024 में टम्प पर हुए जानलेवा हमले की फुटेज दिखाई गई। जिसके साथ एक संदेश था इस बार गोली निशाने से नहीं चूकेगी। यह ट्रम्प के खिलाफ तेहरान की अब तक की सबसे सीधी धमकी है, इससे पहले ट्रम्प ने ही बार-बार ईरान सरकार को धमकी दी है कि अगर वह कार्रवाई जारी रखता है तो अमेरिका उस पर हमला करेगा।

ट्रम्प बोले-

प्रिंस रजा पहलवी अच्छे लगते हैं

ट्रम्प ने बुधवार को कहा कि ईरानी विपक्षी नेता रजा पहलवी उन्हें काफी अच्छे लगते हैं। हालांकि, उन्होंने इस बात पर अनिश्चितता जताई कि उन्हें ईरान के भीतर समर्थन मिल पाएगा और वे नेतृत्व संभाल पाएंगे। रॉयटर्स के अनुसार, ट्रम्प ने कहा, मुझे नहीं पता कि वे अपने देश में कैसे व्यवहार करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति अभी उस स्तर तक नहीं पहुंची है। ट्रम्प ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि ईरानी पहलवी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा,अगर वे स्वीकार करते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। अमेरिका के साथ व्यापक विरोध प्रदर्शनों और तनाव के बीच ईरान ने 2 घंटे के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था।

आई-पैक रेड मामला

ईडी अफसरों पर दर्ज FIR पर 'सुप्रीम' रोक

● ममता सरकार को नोटिस,कहा-एजेंसी के काम में रुकावट न डालें
● यह गंभीर मामला , हम दखल नहीं देंगे तो अराजकता फैल जाएगी

नई दिल्ली (एजेंसी)। आई-पैक रेड मामले में ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से दो हफ्तों के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ईडी के काम में दखल न डालें। एजेंसी को अपना काम करने दें। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- इस मामले में कुछ बड़े सवाल हैं, जिनका जवाब नहीं मिला तो अराजकता फैल सकती है। अगर एजेंसियांईमानदारी से अपना काम कर रही हैं, तो क्या उन्हें राजनीति करके रोका जा सकता है।

● **हाईकोर्ट को जंतर-मंतर बना दिया गया-** ईडी की तरफ से बहस करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 9 जनवरी को कोलकाता हाईकोर्ट को भी भीड़तंत्र का शिकार बनाया गया। हाईकोर्ट में वैसे वकीलों की भीड़ इकट्ठा की गई जिनका केस से कोई संबंध नहीं था। जिसके कारण न्यायाधीश को सुनवाई स्थगित करनी पड़ी। जस्टिस प्रशांत मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की पीठ ने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय को जंतर-मंतर में परिवर्तित कर दिया गया था।

रांची ईडी ऑफिस में जांच करने पहुंची झारखंड पुलिस

● अधिकारियों पर पूछताछ के नाम पर मारपीट का है आरोप

रांची (एजेंसी)। रांची के ईडी ऑफिस में झारखंड पुलिस जांच करने के लिए पहुंची है। दरअसल, ईडी के दो अफसरों पर एक व्यक्ति ने पूछताछ के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। उसकी शिकायत के आधार पर पुलिस ने यह कार्रवाई की है। ईडी

दफ्तर में सदर एडीओपी और एयरपोर्ट थाना के प्रभारी मौजूद हैं। वहीं ईडी ने सुरक्षा के लिहाज से सेंट्रल पुलिस फोर्सेस को बुलाया है। रांची पुलिस की ओर से अब भी जांच चल ही रही है। रांची के चुटिया के संतोष कुमार ने प्रवर्तन निदेशालय के दो अधिकारियों पर मारपीट, जानलेवा हमला, गाली-गलौज और धमकी देने का आरोप लगाते हुए एफआईआर की।

यूपी में कोहरा,4 हादसे, आठ गाड़ियां टकराई, एक की मौत

● शिमला-जम्मू से ज्यादा ठंड, पारा 3 डिग्री,अभी और बिगड़ेगा मौसम

लखनऊ (एजेंसी)। यूपी में कड़ाके की ठंड जारी है। बर्फीली हवाओं की वजह से रात का तापमान शिमला (7 डिग्री) और जम्मू (4.4) से भी नीचे पहुंच गया है। पिछले 24 घंटों के दौरान पूरे प्रदेश में तापमान 10 से नीचे रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान हरदोई सबसे ठंडा रहा, यहां पारा 3 रिकॉर्ड किया गया।

रायबरेली में पारा 3.4, बरेली में 3.5 और कानपुर नगर में 3.8 और अलीगढ़ में 4 डिग्री दर्ज किया गया। इस बीच मौसम विभाग ने 18 जनवरी से बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार सुबह आगरा, बरेली, गाजियाबाद, गोंडा, हाथरस, संभल समेत 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। कई जगह विजिबिलिटी 10 मीटर से भी कम हो गई। कोहरे के चलते 4 भीषण हादसों में एक की मौत हो गई, जबकि करीब 10 लोग घायल हो गए। पहला हादसा मेरठ में

हुआ। यहां देर रात दो कारें टकरा गईं। हादसे में कार ड्राइवर को चोटें आईं। दूसरा- संभल में गन्ने से लदी ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाइक जा घुसी। बाइक सवार की मौत हो गई। तीसरा- कुशीनगर में 3 ट्रक आपस में भिड़ गए। चौथा- बिजनौर में बस सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। इस दौरान 6 यात्री घायल हो गए। गोरखपुर, लखनऊ समेत 50 से ज्यादा ट्रेनें लेट चल रही हैं। वंदे भारत जैसी ट्रेनें भी तय समय से देरी से चल रही हैं। हवाई सफर पर भी कम विजिबिलिटी का असर पड़ा। करीब 10 फ्लाइट्स तय समय से देरी से उड़ीं।

भारतीय पासपोर्ट मजबूत 85 से 80वें नंबर पर आया

55 देशों में वीजा फ्री एंट्री,पाकिस्तानी पासपोर्ट 5वां सबसे कमजोर

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारतीय पासपोर्ट की ताकत पिछले एक साल में बढ़ी है। पासपोर्ट रैंकिंग जारी करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हेनली एंड पार्टनर्स की 2026 की रैंकिंग में भारत 5 स्थान की छलांग लगाकर 80वें नंबर पर पहुंच गया है। पिछले साल 2025 में भारत की रैंक 85 थी। नई रैंकिंग के मुताबिक, भारतीय नागरिक अब 55 देशों में वीजा-फ्री या वीजा-ऑन-अराइवल यात्रा कर सकते हैं। यह रैंकिंग पासपोर्ट धारकों को बिना पूर्व वीजा कितने देशों में प्रवेश की अनुमति है, इसी आधार पर तय की जाती है। इधर पाकिस्तानी पासपोर्ट दुनिया का 5वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। पाकिस्तान की नई रैंकिंग 98वीं है। पिछले साल 2025 में पाक की रैंकिंग 103 थी। वहीं, बांग्लादेशी पासपोर्ट 95 वें नंबर पर है और दुनिया का 8वां सबसे कमजोर पासपोर्ट है। सिंगापुर लगातार दूसरे साल दुनिया का सबसे ताकतवर पासपोर्ट बना हुआ है, जिसे 227 में से 192 देशों में वीजा-फ्री एंट्री है। जापान और दक्षिण कोरिया संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं, इन देशों के नागरिक 188 देशों में बिना वीजा के यात्रा कर सकते हैं। 2025 की रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट 85वें स्थान पर था और 57 देशों तक वीजा-फ्री पहुंच थी। 2024 में भी भारत की रैंक 80 थी। यानी 2025 में गिरावट के बाद 2026 में फिर से सुधार देखने को मिला है। हालांकि, वीजा-फ्री यात्रा में 2 देशों कम हो गए है। 186 देशों में फ्री वीजा एंट्री के साथ डेनमार्क, लक्समबर्ग, स्पेन, स्वीडन और स्विटजरलैंड तीसरे स्थान पर रहे।

आग की चेतावनी ! सिंगापुर जा रही फ्लाइट वापस लौटी

● एयर इंडिया की फ्लाइट में कुल 190 लोग थे सवार

नई दिल्ली (एजेंसी)। सिंगापुर जा रहे एयर इंडिया के एक विमान तकनीकी खराबी आ गई, जिसके बाद इस फ्लाइट को दिल्ली वापस लौटना पड़ा। दिल्ली एयरपोर्ट पर ये विमान वापस लौट आया। सूत्रों ने बताया कि विमान में करीब 190 लोग सवार थे। सूत्रों के अनुसार, ड्रीमलाइनर विमान में एपीयू (ऑक्सिलियरी पावर यूनिट) में आग की चेतावनी मिली, जिसके बाद विमान करीब एक घंटे तक हवा में रहने के बाद दिल्ली लौट आया। पूरा मामला बुधवार देर शाम का है, जब एयर इंडिया के विमान की दिल्ली एयरपोर्ट लैंडिंग हुई। इसके बाद यात्रियों को वैकल्पिक विमान से सिंगापुर भेजा गया। इस संबंध में संपर्क करने पर एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने बताया कि सिंगापुर जा रही उड़ान में हादसा हुआ।

एमपी विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से

19 दिनों की है कार्य अवधि, निपटाए जाएंगे कई काम

भोपाल। मध्यप्रदेश की 16वीं विधानसभा के आगामी बजट सत्र को लेकर इंतजार खत्म हो गया है। राज्यपाल की स्वीकृति के बाद विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना जारी कर दी है। प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह महत्वपूर्ण सत्र 16 फरवरी 2026 से शुरू होकर 6 मार्च 2026 तक चलेगा। कुल 19 दिनों की इस अवधि के दौरान सदन की 14 बैठकें आयोजित की जाएंगी, जिसमें सरकार अपना आगामी वार्षिक बजट पेश करेगी। इस सत्र में विधायकों के वेतन भत्ते बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं। 16 फरवरी को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सत्र की शुरुआत होगी। इसके बाद सरकार द्वारा अनुपूरक बजट और मुख्य बजट के साथ-साथ कई महत्वपूर्ण विधायी विधेयक सदन की

मेज पर रखे जाएंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि विपक्ष ने भी कानून-व्यवस्था, एंबुलेंस सेवाओं की बदहाली और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसे में 19 दिनों का यह सत्र काफी गहमागहमी भरा रहने की उम्मीद है। एमपी विधानसभा सचिवालय ने सत्र की तैयारियों को लेकर सभी विभागों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा ने बताया कि सत्र की सूचना सभी विधायकों को भेज दी गई है और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इस सत्र का सबसे मुख्य आकर्षण वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट होगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की सरकार इस बार महिलाओं और युवाओं के लिए सौगातों का पिटारा खोल सकती है। विशेष रूप से 'लाडली बहना योजना' के लिए बजट में 20 हजार करोड़ रुपये का भारी-भरकम प्रावधान किए जाने की संभावना है, जो पिछले वर्ष के 18,669 करोड़ रुपये से काफी अधिक होगा। इसके अलावा, लखपति दीदी योजना और युवाओं के स्वरोजगार से जुड़ी नई घोषणाएं भी बजट का हिस्सा हो सकती हैं।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य तिलहन मिशन का गठन

भोपाल। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-तिलहन के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य तिलहन मिशन का गठन किया गया है। समिति में कृषि उत्पादन आयुक्त , सहकारिता, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण/ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, वित्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, कुलपति, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर/ राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर, आयुक्त/ संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास, निदेशक भारतीय सोयाबीन अनुसंधान संस्थान, इन्दौर म.प्र, प्रभारी अधिकारी नाबार्ड, समन्वयक स्टेट लेवल बैंकर समिति, तिलहन क्षेत्र में कार्यरत एफपीओ/ को-ऑपरेटिव्स के दो प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक), बीज एवं खाद्य तेल उत्पादक उद्योग से संबंधित दो प्रतिनिधि (प्रत्येक से एक-एक), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय द्वारा नामित अधिकारी सदस्य होंगे। किसान कल्याण तथा कृषि विकास को सदस्य-सचिव नामित किया गया हैं।

बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज

भोपाल। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा भोपाल शहर वृत्त के पूर्व शहर संभाग अंतर्गत बाग फरहत अफजा ऐशबाग में बिजली कर्मचारियों के साथ मारपीट करने वाले तीन आरोपितों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कंपनी के इंडस्ट्रियल गेट कार्यालय प्रबंधक श्री संजय बारमासे ने बताया कि बाग फरहत अफजा निवासी श्रीमती शहजादी बी द्वारा विद्युत देयक बकाया 1 लाख 41 हजार 669 रुपए जमा नहीं किया जा रहा था। उन्होंने उक्त मकान सीमा बेगम को विक्रय कर दिया। सीमा बेगम को बताया गया कि आपके द्वारा क्रय किये गये मकान का विद्युत देयक बकाया है। यदि बकाया देयक जमा नहीं किया तो विद्युत विच्छेदन की कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद उन्होंने शासकीय कार्य में बाधा डालते हुए कर्मचारियों को अभद्रता की और मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इस पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा आरोपितों सीमा बेगम, श्री आशु एवं श्री समीर के खिलाफ ऐशबाग थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 296(बी), 132, 351(3) , 3(5) में एफआईआर दर्ज कराई गई है। थाना एशबाग ने भी प्रकरण पर संज्ञान लेकर विवेचना शुरू कर दी है। बिजली कंपनी के मैदानी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने तुरन्त एफ.आई. आर. कराने के निर्देश दिए हैं। कंपनी ने कहा है कि प्रायः देखने में आ रहा है कि बिजली कर्मियों पर ड्यूटी के दौरान असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट/दुर्व्यवहार किया जा रहा है।

अपनी सांस्कृतिक अनुभूतियों का देश हित में करें उपयोग : राज्यपाल

राज्यपाल से मिले सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट्स

भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा है कि प्रशिक्षण, अधिकारियों को सशस्त्र सीमा बल के लिये केवल अधिकारी नहीं, बल्कि एक जिम्मेदार, संवेदनशील और सजग राष्ट्र-प्रहरी के रूप में तैयार करने का समन्वित प्रयास है। प्रशिक्षण, व्यक्तित्व निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह सभी प्रशिक्षणार्थियों को एक-दूसरे के राज्य की संस्कृति, विशेषताओं और विविधताओं को समझने का अवसर प्रदान करता है। विविधता में एकता की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु अपने राज्य की विशिष्टताओं की अनुभूतियों और प्रशिक्षण के निर्देशों का देश हित में उपयोग कर, 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के निर्माण में योगदान दे। राज्यपाल श्री पटेल गुरूवार को सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल के प्रशिक्षु सहायक कमांडेंट्स को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को राष्ट्र के प्रतिष्ठित बल में चयन की बधाई और शुभकामनाएं दी। लोकभवन में आयोजित सौजन्य भेंट कार्यक्रम में राज्यपाल के प्रमुख सचिव डॉ. नवनीत मोहन कोठारी भी मौजूद थे। राज्यपाल श्री पटेल ने प्रशिक्षणार्थियों से कहा कि आप सभी उन सौभाग्यशाली लोगों में शामिल हैं, जिन्हें सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल का हिस्सा बनकर माँ भारती की सेवा का अवसर मिला है। आपकी वर्दी केवल पहचान नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के सम्मान का प्रतीक है। इसी वर्दी के साये में देशवासी स्वयं को सुरक्षित महसूस करते हैं। आप जब अपने परिवार से दूर सीमाओं पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं, तभी हर देशवासी चैन और शांति की नींद सो पाता है। उन्होंने कहा कि ईमानदारी, निष्पक्षता और संवेदनशीलता के साथ कर्तव्यों का पालन करने वाले अधिकारी ही समाज में विश्वास और सम्मान अर्जित करते हैं। आप सभी निष्ठा, समर्पण और साहस के साथ राष्ट्र की सेवा करें।

भोपाल की गौरवशाली परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएं

सशस्त्र सीमा बल अकादमी भोपाल की गौरवशाली परंपरा को नई ऊँचाइयों तक पहुंचाएं। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में देश के समक्ष आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, नक्सलवाद, तस्करी, साइबर अपराध और असामाजिक गतिविधियाँ जैसी अनेक महत्वपूर्ण चुनौतियां है। राष्ट्र प्रहरी के रूप में आपके निर्णय और कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपनी प्रतिभा से सीमा सुरक्षा प्रबंधन में आधुनिक तकनीक, व्यावसायिक ज्ञान, शारीरिक और मानसिक सक्रियता के नए मानक स्थापित करे। यह सुनिश्चित होना चाहिए कि असामाजिक और राष्ट्र-विरोधी तत्वों पर कठोरता से नियंत्रण करें। राज्यपाल श्री पटेल ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारियों का निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करें। उनके अनुभवों से सीखें और अपने ज्ञान को सहकर्मियों के साथ साझा भी करें। राज्यपाल श्री पटेल का एस.एस.बी. अकादमी भोपाल के निदेशक श्री बी.एस. जायसवाल ने पौधा भेंट कर स्वागत और स्मृति चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया। एस.एस.बी. अकादमी भोपाल निदेशक श्री जायसवाल ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। प्रशिक्षु अधिकारी सुश्री अनुष्का मनियारा और श्री अनुराग भार्गव ने प्रशिक्षण में अनुभवों को साझा किया। कमांडेंट प्रशिक्षण श्रीमती सुवर्णा सजवाल ने आभार व्यक्त किया। कोर्स डायरेक्टर डिप्टी कमांडेंट प्रशिक्षण श्री रोहित शर्मा ने कार्यक्रम का संचालन किया। सौजन्य भेंट कार्यक्रम में राज्यपाल के अपर सचिव श्री उमाशंकर भार्गव, लोकभवन और एस.एस.बी. के अधिकारी-कर्मचारी एवं प्रशिक्षु अधिकारी उपस्थित थे।

थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों का अब फ्री में होगा इलाज

मेदांता फाउंडेशन और एनएचएम के बीच हुआ करार, 8 लाख से कम आय वाले होंगे पात्र

भोपाल। थकान, त्वचा और आंखों का पीला पड़ना, सांस लेने में तकलीफ और पेट में सूजन थैलेसीमिया के लक्षण हैं। इसके MP में 2 हजार से अधिक रजिस्टर केस हैं। करीब 1800 मरीज नियमित रूप से ब्लड सेंटर्स जाकर ट्रांसफ्यूजन कराते हैं। सरकार ने पहली बार इस स्थिति को गंभीरता से लिया है। इसका जिलेवार डेटा जुटाया जा रहा है। मेदांता फाउंडेशन और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) ने फोटो-HLA टेस्ट से लेकर बोन मैरो ट्रांसप्लांट तक की सुविधा मुफ्त में उपलब्ध कराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए हाल ही में एक MOU भी किया गया है। मध्यप्रदेश में थैलेसीमिया के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन अधिकांश परिवारों को यह भी नहीं पता कि इलाज सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन तक सीमित नहीं है। विशेषज्ञों का कहना है कि थैलेसीमिया के रोगी यदि पात्र हों तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट (BMT) के जरिए पूरी तरह ठीक हो सकते हैं। अपना आगे का जीवन सामान्य रूप से जी सकता है। NHM से मिली जानकारी के अनुसार इलाज में देरी या लापरवाही से शरीर में आयरन ओवरलोड हो जाता है, जो हृदय, लिवर और एंडोक्राइन सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकता है।

एमपी सरकार जुटा रही जिला-वार डेटा

थैलेसीमिया मामलों की सही तस्वीर सामने लाने के लिए सरकार ने जिला स्तर पर डेटा कलेक्शन शुरू किया है। लक्ष्य यह है कि कितने बच्चे ट्रांसफ्यूजन पर हैं, किस उम्र में बीमारी सामने आई, परिवार की आर्थिक स्थिति क्या है और कौन BMT के लिए पात्र है। स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि जिलेवार आंकड़े मिलने पर हर बच्चे की मेडिकल-स्किल बेस्ड योजना बनाई जा सकेगी और समय रहते हस्तक्षेप किया जा सकेगा।

माता-पिता से बच्चों में आता है थैलेसीमिया

थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रक्त विकार है जो माता-पिता से बच्चों में आता है। इस बीमारी में शरीर में हीमोग्लोबिन सही मात्रा में नहीं बनता। परिणामस्वरूप शरीर में खून की कमी हो जाती है और मरीज को धीरे-धीरे रक्त चढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर बताते हैं कि औषधि और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बीमारी नियंत्रित रखी जा सकती है, परंतु इसका पूर्ण इलाज बोन मैरो ट्रांसप्लांट ही है। इसलिए जागरूकता, समय पर पहचान और सही उपचार महत्वपूर्ण है। प्रदेश के थैलेसीमिया बच्चों को निःशुल्क बोन मैरो ट्रांसप्लांट सुविधा देने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश और मेदांता फाउंडेशन नई दिल्ली के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के अनुसार प्रथम चरण में इंदौर, उज्जैन और देवास जिले कवर होंगे। इसके बाद बच्चों और उनके भाई व बहनों की HLA टाइपिंग होगी, पात्रता की पुष्टि के बाद मरीजों को दिल्ली भेजा जाएगा और बोन मैरो ट्रांसप्लांट पूरी तरह मुफ्त होगा। इसके साथ ही आवाजाही और आवास का खर्च भी नहीं लगेगा। यह योजना कोल इंडिया थैलेसीमिया बाल सेवा योजना के तहत चलाई जा रही है।

इंदौर नंबर-1 था, है और हमेशा रहेगा

भागीरथपुरा की घटना के बाद दहाड़े कैलाश

इंदौर। मध्यप्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रमुख विपक्षी दल राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर के लगातार आठ बार पर अव्वल रहने के बारे में बेबुनियाद सवाल उठाकर शहर की जनता और सफाई कर्मियों का अपमान कर रहा है। दूषित पेयजल के कारण फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप से कई लोगों की मौत को लेकर सुर्खियों में चल रहा शहर का भागीरथपुरा इलाका विजयवर्गीय के विधानसभा क्षेत्र 'इंदौर-1' में आता है। इस घटनाक्रम के बाद से वह कांग्रेस के निशाने पर चल रहे हैं। राज्य के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इंदौर में एक कार्यक्रम के दौरान प्रमुख विपक्षी दल पर पलटवार करते हुए कहा कि एक घटना को लेकर आप इंदौर की जनता की बदनामी कर रहे हैं और शहर के सफाई कर्मियों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपकी मां, बहन और बेटी रात के दो बजे घर से निकलकर सड़क पर सफाई कर सकती हैं? ये इंदौर के सफाई कर्मी हैं जो अपनी महिलाओं को शहर को स्वच्छ करने के लिए रात के दो बजे भी भेजते हैं।

फर्जी दस्तावेजों का कर रही इस्तेमाल

प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने भागीरथपुरा में दूषित पेयजल के सेवन से कई लोगों की मौत के बाद हाल ही में दावा किया है कि सरकारी अधिकारियों ने फर्जी दस्तावेज पेश करके इंदौर को स्वच्छता के सिलसिलेवार खिताब दिलाए हैं। विजयवर्गीय ने सिंघार का नाम लिए बगैर कहा कि कांग्रेस नेताओं को यह बोलने से पहले शर्म आनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर को अव्वल बनाने के लिए गलत दस्तावेज पेश किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी बातें बोलना स्वच्छता के लिए इंदौर की जनता की भागीदारी का भी अपमान है। इन बेशर्मों को शहर के सफाई कर्मियों और जनता से माफी मांगनी चाहिए। विजयवर्गीय ने जोर देकर कहा कि स्वच्छता के मामले में इंदौर 'नम्बर 1' था, है और हमेशा रहेगा। काबीना मंत्री ने कांग्रेस नेताओं को किसी भी सार्वजनिक मंच पर बहस की चुनौती देते हुए कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में शहर के हित में कौन-से काम किए हैं? विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग्य से छींका टूट गया। ऐसे में बिल्ली की तो दीपावली हो गई। बिल्ली की भले ही दीपावली हो गई, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि शहर की आन-बान-शान जाने नहीं देंगे। गौरतलब है कि प्रशासन ने भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से फैले उल्टी-दस्त के प्रकोप में अब तक छह लोगों की मौत की आधिकारिक पुष्टि की है, जबकि स्थानीय नागरिकों ने इस प्रकोप के कारण छह माह के बच्चे समेत 23 मरीजों के दम तोड़ने का दावा किया है। मृतकों की तादाद को लेकर विरोधाभासी दावों के बीच, शहर के शासकीय महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय की एक समिति के किए गए 'डेथ ऑडिट' की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि भागीरथपुरा के 15 लोगों की मौत उल्टी-दस्त के प्रकोप से किसी न किसी तरह जुड़ी हो सकती है।

भोपाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन भिड़े, 5 की मौत

सभी मृतक एक ही परिवार के, अंतिम क्रिया के लिए नर्मदापुरम जा रहे थे

भोपाल। भोपाल में ट्रैक्टर-ट्रॉली और लोडिंग वाहन के बीच आमने-सामने की टक्कर में 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। 12 घायल हुए हैं। हादसा बैरसिया थाना इलाके में बुधवार रात करीब साढ़े 9 बजे हुआ। घायलों में से कुछ की हालत गंभीर है। टीआई वीरेंद्र सेन ने बताया कि सिरोंज के एक ही परिवार के 15 लोग लोडिंग वाहन में थे। इनमें से पांच की मौत हो गई है। नौ घायल हुए हैं। ट्रैक्टर सवार 3 लोग भी घायल हुए हैं। सभी घायलों को बैरसिया शासकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लोडिंग वाहन में सवार परिवार किसी परिजन की अंतिम क्रिया के लिए नर्मदापुरम जा रहा था। जैसे ही उनका वाहन बैरसिया थाना इलाके में ठाकुर लाल सिंह स्कूल के पास पहुंचा, सामने से आ रही ट्रैक्टर-ट्रॉली से टक्कर हो गई। इसमें लोडिंग

वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। उसमें सवार कई लोग अंदर ही फंस गए। बैरसिया एसडीएम आशुतोष शर्मा, एएसपी नीरज चौरसिया और बैरसिया टीआई वीरेंद्र सेन समेत विधायक विष्णु खत्री अस्पताल पहुंचे। घायलों के उचित इलाज के निर्देश दिए। एसडीएम शर्मा ने कहा- शुरुआती जांच में तेज रफ्तार को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि, वास्तविक कारण जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

भोपाल में बीसीए फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाई

मां से बोला-मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूं अपना ध्यान रखना

भोपाल। भोपाल के वल्लभ नगर में रहने वाले बीसीए फाइनल ईयर के छात्र ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। बुधवार रात छात्र का शव उसके कमरे से मां की साड़ी से बने फंदे पर लटका मिला। छात्र ने जन्मदिन के दिन ही खुदकुशी की। सुसाइड से पहले उसने मां को कॉल कर बताया कि मैं जान दे रहा हूं...अपना ख्याल रखना। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सुशील चौरसिया (23) पुत्र रामस्वरूप चौरसिया वल्लभ नगर में रहता था और एक प्राइवेट कॉलेज से बीसीए फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा था। उसके मां और पिता रातीबड़ इलाके में नया मकान बनवा रहे हैं। दोनों बुधवार सुबह से वहां चले गए थे। सुशील का बुधवार को जन्मदिन था, रात के समय दोस्तों ने उसके लिए पार्टी रखी थी। दोस्त इसकी तैयारी में थे। उसके दोनों बड़े भाई अपने-अपने काम पर चले गए थे। युवक घर में अकेला था। शाम के समय उसने मां को कॉल कर कहा कि मैं बहुत दूर रहा हूं। अपना ध्यान रखना, मां

ने उसे समझाइश दी। जब मां और पिता घर लौटे तो बेटे के शव को फंदे पर लटका हुआ देखा। गुरुवार को पीएम के बाद बॉडी को परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है।

पानी में 'जहर' और 15 लाख पेड़ों की बलि

एनजीटी ने सरकार से कहा-ऐसा नहीं चलेगा

भोपाल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पेयजल की बदहाली और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ पर बेहद कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने इन तीन राज्यों की सरकारों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने माना है कि लोगों के घरों तक पहुंचने वाला पानी अब पीने लायक नहीं बचा है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि पुरानी और जर्जर पाइप लाइनों की वजह से सीवेज का गंदा पानी पेयजल में मिल रहा है। इंदौर और भोपाल में खौफनाक मंजर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल और मिनी मुंबई कहे जाने वाले इंदौर से डराने वाली खबरें हैं। इंदौर में गंदे पानी के सेवन से मौतें होने का हवाला दिया गया है, वहीं भोपाल के कई इलाकों में 'ई-कोलाई' जैसे खतरनाक बैक्टीरिया पाए गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक, भोपाल के आदमपुर और हरिपुरा जैसे क्षेत्रों में भूजल पूरी तरह प्रदूषित हो चुका है, जिससे लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में हैं। एक तरफ पानी में जहर घुल रहा है, तो दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में विकास के नाम पर हरियाली का गला घोंटा जा रहा है। एनजीटी ने संज्ञान लिया है कि सड़कों, रेलवे और कोयला खदानों के लिए एमपी में करीब 15 लाख पुराने पेड़ों को काटा जा चुका है या काटने की तैयारी है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन और विदिशा जैसे शहरों में इस भारी कटाई के कारण हवा (AQI) भी अब जहरीली होने लगी है। सरकार से जवाब तलब एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और डॉ. ए. सेंथिल वेल ने इस मामले को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और जल प्रदूषण अधिनियम का गंभीर उल्लंघन माना है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट कर दिया है कि नागरिकों को सुरक्षित पानी देना सरकार की जिम्मेदारी है और इस लापरवाही पर जवाबदेही तय की जाएगी।

एमपी में राजगढ़ सबसे ठंडा, टेम्प्रेचर 5.5 डिग्री

इंदौर जिले में एक ही रात 3.4 डिग्री लुढ़का पारा, वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मावठा गिरने के बने आसार

भोपाल। मध्यप्रदेश में ठंड का असर फिर बढ़ गया है। बुधवार रात राजगढ़ प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा। यहां पर न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री रहा। इंदौर में पारे में एक ही रात में 3.4 डिग्री की गिरावट हुई और यह 6.8 डिग्री पर आ गया। प्रदेश के सभी 5 बड़े शहर- इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में तापमान फिर से 10 डिग्री से नीचे आ गया है। बुधवार-गुरुवार की रात में भोपाल में 8 डिग्री, ग्वालियर में 7.4 डिग्री, उज्जैन में 9 डिग्री और जबलपुर में तापमान 9.8 डिग्री रहा। वहीं, रीवा में 6.2 डिग्री, दतिया में 6.6 डिग्री, पचमढ़ी में 6.8 डिग्री दर्ज किया गया। उमरिया, नौगांव, मंडला, खजुराहो, सतना, दमोह, सीधी, रायसेन, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, मलाजखंड और रतलाम में भी तापमान 10 डिग्री से कम

रहा। सुबह ग्वालियर में घना कोहरा छाया रहा। यहां विजिबिलिटी 1 हजार मीटर तक रही। भोपाल, दतिया, गुना, इंदौर, उज्जैन, खजुराहो, रीवा, सतना, राजगढ़, रतलाम, जबलपुर, सागर, शाजापुर, सीहोर, रायसेन, विदिशा, छतरपुर समेत कई जिलों में मध्यम कोहरा छाया रहा। प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी, ग्वालियर, चंबल, सागर और रीवा संभाग में कोहरे का असर बरकरार है। गुरुवार सुबह ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना और रीवा में मध्यम कोहरा छाया रहा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रायसेन, सीहोर, शाजापुर, सतना, गुना, राजगढ़, रतलाम, मंडला समेत कई जिलों में हल्का कोहरा रहा। कोहरे की वजह से दिल्ली से भोपाल, इंदौर और उज्जैन आने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से लेट हो रही है। इनमें सबसे ज्यादा असर मालवा, झेलम और सचखंड एक्सप्रेस में हो रहा है। इसके अलावा पंजाब मेल, जन शताब्दी समेत एक दर्जन ट्रेनें भी प्रभावित हो रही है।

कल्याणपुर-करौंदी सबसे ठंडे, ग्वालियर में 7.1 डिग्री दर्ज

प्रदेश के उत्तरी हिस्से में ठंड और कोहरे का असर है। मंगलवार-बुधवार की रात शहडोल के कल्याणपुर में 4.8 डिग्री और कटनी के करौंदी में 4.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रीवा में 5.8 डिग्री, मंदसौर-चित्रकूट में 6.1 डिग्री, खजुराहो में 6.2 डिग्री, उमरिया में 6.8 डिग्री, दतिया-मंडला में 7 डिग्री, राजगढ़-नौगांव में 7.2 डिग्री, पचमढ़ी में 7.8 डिग्री, शिवपुरी में 8 डिग्री, दमोह-सीधी में 9 डिग्री, रायसेन-श्योपुर में 9.4 डिग्री रहा। प्रदेश के 5 बड़े शहरों की बात करें तो ग्वालियर सबसे ठंडा रहा। यहां न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री दर्ज किया गया। भोपाल में 9.8 डिग्री, इंदौर में 10.2 डिग्री, उज्जैन में 11.2 डिग्री और जबलपुर में तापमान 10 डिग्री दर्ज किया गया।

कोल्ड वेव या कोल्ड डे का अलर्ट भी नहीं

मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार को प्रदेश में कहीं भी कोल्ड वेव यानी, शीतलहर का अलर्ट नहीं है। न ही कहीं कोल्ड डे रहेगा। इस बार मध्यप्रदेश में नवंबर-दिसंबर की सर्दी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। नवंबर में 84 साल में सबसे ज्यादा ठंड पड़ी तो दिसंबर में 25 साल का रिकॉर्ड टूटा। नवंबर-दिसंबर की तरह ही जनवरी में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। इससे भोपाल में ठंड का 10 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। एक्सपर्ट की माने तो जनवरी में प्रदेश में माइनस वाली ठंड गिर चुकी है। अबकी बार भी तेज सर्दी, घना कोहरा छाने के साथ शीतलहर भी चल रही है।

संपादकीय

चाइनीज मांझे पर सख्ती से आगे की राह

बरसों से मकर संक्रांति और पतंग उड़ाने का उत्सव भारत के हर कोने में धूमधाम से मनाया जाता रहा है। लेकिन, हाल के वर्षों में यह पारंपरिक शौक जानलेवा बन गया। चाइनीज मांझा, जो कांच और धातु के जहरीले मिश्रण से बना होता है, गर्दन रेत रहा है, आंखें फोड़ रहा है और कई बार मौत का पैगाम लेकर आ रहा है। इंदौर, दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में ऐसी घटनाएं आम हो गई, जहां साधारण पतंगबाजी दुर्घटना में बदल गई। प्रशासन ने प्रतिबंध लगाया, पुलिस सक्रिय हुई, लेकिन क्या यह काफी है? समस्या की जड़ चाइनीज मांझे के उत्पादन और आयात में है, जिसे रोकना होगा। केवल बिक्री और खरीद पर रोक से यह काला बाजार खत्म नहीं होगा। चाइनीज मांझे की खतरनाक प्रकृति समझना जरूरी है। पारंपरिक मांझा सूत पर कांच का लेप होता था, जो पर्यावरण-अनुकूल और कम घातक था। लेकिन, चीन से आयातित यह मांझा प्लास्टिक कोटिंग के साथ कांच, एल्युमिनियम और कभी-कभी ब्रोमीन जैसे रसायनों से बना होता है। यह इतना तेज होता है कि बाइक सवारों की गला काट देता है, पक्षियों को मार गिराता है और बच्चों को गंभीर चोटें पहुंचाता है। हाल के सालों में मध्य प्रदेश में दर्जनों ऐसे मामले सामने आए, जहां पतंगबाजी के दौरान लोग शिकार बने। एनजीटी ने भी इसे पर्यावरण के लिए हानिकारक घोषित किया। फिर भी, सस्ते दाम और आसानी से उपलब्धता के कारण इसका चलन बढ़ता जा रहा है। प्रशासन प्रतिबंध लगाता है, लेकिन स्थानीय बाजारों में 'चीनी धागा' या 'सुपर मांझा' नाम से यह बिकता रहता है। क्योंकि, प्रशासनिक प्रयासों की कमी है। मकर संक्रांति से पहले पुलिस अभियान चलाती है, दुकानों पर छापे मारती है, लाखों मीटर मांझा जब्त करती है। इंदौर में चाइनीज मांझा पकड़ा गया। लेकिन प्रतिबंध केवल सतही है। दंड संहिता के तहत जुर्माना या जेल की धमकी दी जाती है, पर अमल ढीला रहता है। विक्रेता छोटे-छोटे ठेले या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं, जबकि खरीदार उत्सव की धूम में लापरवाह हो जाते हैं। समस्या यह है कि प्रतिबंध बिक्री और उपयोग तक सीमित है, स्रोत तक नहीं पहुंचते। चाइनीज मांझा मुख्यतः चीन के गुआंगझू और यिवू जैसे बाजारों से भारत आता है, जो ई-कॉमर्स, अनौपचारिक आयात या स्थानीय नकली उत्पादन के जरिए देश में घुसता है। कस्टम विभाग जब्ती करता है, लेकिन मात्रा विशाल है। 2024 के आंकड़ों के अनुसार, भारत में सालाना करोड़ों मीटर चाइनीज मांझा आता है। इसके समाधान के लिए बहुआयामी रणनीति जरूरी है। सबसे पहले, स्रोत पर चोट करनी होगी। विदेश व्यापार महानिदेशालय को चाइनीज मांझे के आयात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, जैसा कि प्लास्टिक प्रदूषण पर हुआ। कस्टम्स को विशेष निगरानी यूनिट गठित करनी चाहिए, जो डाक, कूरियर और ऑनलाइन आयात पर नजर रखे। स्थानीय स्तर पर नकली उत्पादन रोकने हेतु फैक्ट्रियों की जांच अभियान चलाएं। केवल दमन से काम नहीं चलेगा; जागरूकता अभियान जरूरी है। स्कूलों, कॉलोनियों में वर्कशॉप आयोजित कर पारंपरिक मांझे का प्रचार करें। 'चीनी मांझा मुक्त संक्रांति' जैसे कैंपेन चलाकर विक्रेताओं को वैकल्पिक रोजगार दें, जैसे जैविक मांझा निर्माण। मध्य प्रदेश सरकार में कुछ हद तक सख्ती तो हुई, पर इतनी प्रभावी नहीं कि ऐसे जानलेवा मांझे पर रोक लग सके। कानूनी सख्ती के साथ सामाजिक भागीदारी भी महत्वपूर्ण है। एनजीओ और समाजसेवी क्लब और पक्षी संरक्षण वाले संगठनों को सक्रिय किया जाए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो दिखाकर खतरे का अहसास कराएं। यदि स्रोत रोका गया, तो बिक्री खुद बंद हो जाएगी। उदाहरण यह है कि गुजरात में सामुदायिक प्रयासों से चाइनीज मांझा 70% कम हुआ। केंद्र सरकार को 'पतंग नीति' बनानी चाहिए, जो आयात से उत्पादन तक नियंत्रित करे। यह केवल प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं। उत्सव की खुशी में सुरक्षा का ध्यान रखें। चाइनीज मांझा रोकना है तो स्रोत को सुखाना होगा, न कि केवल पेड़ के पत्ते काटना। तभी हमारा पारंपरिक शौक फिर से सुरक्षित बनेगा।

असहिष्णु पीढ़ी से नाउम्मीद होता भारत

भारतीय पढ़े-लिखे लोगों में असहिष्णु मन कुछ ज्यादा ही हावी होने लगे हैं। किसी को भी धैर्य नहीं है। सब अधीर हो रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण पहले विश्वविद्यालय कैम्पस में नहीं होते थे। लोगों के भीतर सहन-शक्ति तो होती ही थी। वे अपने आपको प्रतिबद्ध करके कार्यक्रम में मनोयोग से बैठे होते थे। अब देश में विश्वविद्यालय कैम्पस बहुत ही शोर व अधीर से हो गए हैं। इस देश में विश्व गुरू बनते विश्वविद्यालयों की अब यह हालत देखकर लगता है कि इनकी रैंकिंग अब अपनी अधीरता के मापांक पर पहले हो जाएगी और पठन-पाठन, शोध व साधना के लिए विश्व में 500वीं रैंक से बाहर हो जायेगी।

नजरिया
प्रो. कन्हैया त्रिपाठी
लेखक राष्ट्रपति के विशेष कार्य अधिकारी रह चुके हैं और केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब में चेयर प्रोफेसर हैं।

बीते दिनों गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में एक साहित्यिक संगोष्ठी के दौरान जिस प्रकार की असहिष्णुता सामने आई, वह किसी को भी अप्रिय लगेगी। विश्वविद्यालय की अपनी गरिमा होती है। उसके अपने अनुशासन होते हैं। विश्वविद्यालय कैम्पस में शिक्षार्थी, शोधार्थी और प्रशासन के लोगों का अपना आकाश होता है। इस विद्या मंदिर में कुलपति जी का अपना एक औरा होता है। किसी विश्वविद्यालय कैम्पस में कार्यक्रम की भी अपनी गरिमा होती है। लेकिन जहाँ सभी लोग पढ़े-लिखे बैठे हो, वहीं से एक ऐसी वीडियो वायरल हुई जो देश में चर्चा की विषय बन गयी। चर्चा होती भी क्यों नहीं बात ही कुछ इस प्रकार की उस सभागार में हो गयी।

भारतीय पढ़े-लिखे लोगों में असहिष्णु मन कुछ ज्यादा ही हावी होने लगे हैं। किसी को भी धैर्य नहीं है। सब अधीर हो रहे हैं। इस प्रकार का वातावरण पहले विश्वविद्यालय कैम्पस में नहीं होते थे। लोगों के भीतर सहन-शक्ति तो होती ही थी। वे अपने आपको प्रतिबद्ध करके कार्यक्रम में मनोयोग से बैठे होते थे। अब देश में विश्वविद्यालय कैम्पस बहुत ही शोर व अधीर से हो गए हैं। इस देश में विश्व गुरू बनते विश्वविद्यालयों की अब यह हालत देखकर लगता है कि इनकी रैंकिंग अब अपनी अधीरता के मापांक पर पहले हो जाएगी और पठन-पाठन, शोध व साधना के लिए विश्व में 500वीं रैंक से बाहर हो जायेगी। देश में यह माहौल उस समय पनपा है जब देश के प्रधान मंत्री प्रत्येक दिन भारत के विकसित होने की बात कर रहे हैं और वह चाहते हैं की 2047 तक कम से कम भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में पहुँच जाए।

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की अब बात की जाए तो वहां जो कुलपति द्वारा एक नामचीन साहित्यकार को सभागार छोड़कर जाने को कहा गया उस पर बहुत ही गंभीर तरीके से प्रतिक्रिया अखिल भारतीय स्तर पर दर्ज की गयी। ऐसा लगा की यह ऑपरेशन सिंदूर की भांति गोले-तोप व मिसाइल से हमले शुरू हो गए हैं। लंबी पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब लिखी गयी। अधिकांश सोशल मीडिया पर लिखी गयी टिपण्णी मनोज रूपड़ा के पक्ष में लिखे गए और कुलपति प्रो। आलोक चक्रवाल के खिलाफ प्रकाशित की गयी। अधिकांश बौद्धिक समाज कहलाने वाला वर्ग रूपड़ा को संयमित, विनम्र और सही टिप्पणी करने के लिए स्मरण किया और उनकी पीठ थपथपाई। कुलपति के खिलाफ जितनी भी बातें हो सकती थी, सब कह दिया। कुछ लोग कुलपति चक्रवाल के अतीत को झांकना, कुछ निकालना और उस पर बरसना शुरू कर दिए। एक लंबा जीवन जीकर कोई भी कुलपति बनता है तो छोटे-बड़े उतार चढ़ाव के बाद ही इस पद तक पहुँचता है। उसके जीवन के अनेक ऐसे पल होते हैं जो संघर्ष, आरोप-प्रत्यारोप में बीते होते हैं। अब भला कौन सा व्यक्ति ऐसा है जिसे डिटर्जेंट में धोकर सरकारें कुलपति बनाती हैं। सभी के ऊपर कोई न कोई आरोप लगाने वाला होता है और कोई न कोई काम नहीं होने देने के सौगंध के साथ कुछ नहीं करेगा तो उसकी कैसे फजीहत हो सकती है, इसके पीछे पूरी ऊर्जा खपत करता है। ऐसी स्थिति में सरकारें जब कुलपति की नियुक्ति करेगी तो कहाँ से कुलपति लाएगी, आकाश से, एआई से या पाताल से क्योंकि पृथ्वी के लोगों में गुण और दोष तो उनके जीवन का हिस्सा होते हैं।

खैर, उस दिन जो कार्यक्रम था वह साहित्य अकादमी के सहयोग से हो रहा था। हिंदी विभ्भाग आयोजक था स्थानीय स्तर पर और स्वाभाविक रूप से कुलपति प्रो। आलोक चक्रवाल उस कार्यक्रम में किसी न किसी रूप में सम्मिलित होंगे। एक कुलपति के अपने जीवन के प्रसंग भी होते हैं, उसे उन्होंने सुनना शुरू किया और उनके मन में जब थोडा देरी होने पर एक बात आई कि और वह भी स्वतःस्फूर्त ही लगी कि उन्होंने पूछा कि क्यों आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? इस पर तपाक से कहानीकार मनोज रूपड़ा ने कह दिया विषय पर आप आइये तो अच्छा होता। मनोज रूपड़ा को यह कदाचित नहीं बोलना चाहिए था। जिस कैम्पस में आप बैठे हैं उस कैम्पस के मुख्य अधिकारी प्रशासनिक व अकादमिक रूप से कुलपति ही होते हैं।

उन्हें इतनी प्रिविलेज होती ही है कि वह चाहे जितना समय लें, लेकर बोलें। लेकिन मनोज रूपड़ा को लगा की वह अपने लेखक मंडली में बैठे हैं और जो उनके मन में है वह दोस्त से बात कर रहे हैं। यह बात उन्हें अपने समकक्ष लोगों के साथ बोलते हुए सुनना अच्छा लगता है लेकिन कुलपति के लिए उनका इस प्रकार कहना किसी भी प्रकार से उचित नहीं था। उन्हें इस बात का भान अगर होता कि वह एक ऐसे सभागार में बैठे हैं जिसका संरक्षक प्रशासकीय व अकादमिक रूप से कुलपति ही है तो वह यह नहीं बोलते लेकिन लेखकों की बिरादरी भी अपनी मर्यादा कभी कभी भूल जाती है और वह कुछ भी बोल जाती है, यह एक सचाई है।

विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी संगोष्ठी व सम्मेलन में प्रतिभागिता करते हुए लेखक हों या कोई सरकार में मंत्री व प्रशासन के लोग सबको यह ख्याल रखना चाहिए कि यह उनकी अपनी सर्किल नहीं है अपितु यह एक अकादमिक स्थल है और अकादमिक स्थल में विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षक हैं। उन पर हमारे बोलने का असर होगा। हम मर्यादित होकर गरिमा के अनुकूल संसदीय व शिष्ट ही होकर पेश आयें। लेकिन असहिष्णु व बेचैन इस समय की कोई भी कम्युनिटी हो यह नहीं सोच रही है कि वह कहाँ बैठी है और क्या बोल रही है। उसके आचरण किसको प्रभावित करने जा रहे हैं। प्रायः हमने कई कार्यक्रमों में देखा कि जो भी ऑडियंस है वह बार-बार अपनी मोबाईल देखती है। शिक्षक भी देखते हैं और कुलपति भी। इतनी अगर आपके पास समय की कमी है और आप इतने ही व्यस्त हैं तो ऐसी कार्यक्रमों में जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रधान मंत्री भी प्रत्येक दिन कार्यक्रम में रहते हैं और वह मोबाईल देखा करें तो कभी भी वह इतने सारे कार्यक्रमों में न जा सकेंगे और न कुछ बोल सकेंगे न ही उस कार्यक्रम की गरिमा ही रहेगी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये जो लोग बार-बार अपनी मोबाइल से खुद व अपने आस-पास के लोगों को प्रभावित करते हैं, वे प्रधान मंत्री से भी अधिक विजी हैं?

इस बेचैन, अधीर और असहिष्णु खेप से तो भारत का भला होना नहीं है, एक बात तो तय है। कुलपति प्रो। चक्रवाल को भी थोडा सा संयम दिखाना चाहिए था लेकिन अगर वे उस सभागार में छोड़ देते मनोज रूपड़ा को कुछ बिना कहे तो वह जिंदगी भर यह कहते कि हम गुरू घासीदास विश्वविद्यालय में गए थे और कुलपति ने मुझसे पूछा तो हमने तो वहीं उनको लताड़ दिया था। इसलिए भी चक्रवाल ने जो कहा वह उचित है और विश्वविद्यालय परिसर में किस प्रकार की बातें होनी चाहिए और किस तरह की नहीं होनी चाहिए उस पर उनका एक प्रशासनिक तरीके का सन्देश है जिसे किसी दबाव में आकर एकदम से गलत भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन सहिष्णुता कैसे कायम होगी, इस पर हमारी चिंता आज बढ़ गयी है और देश का भला कैसे होगा अब यह भी चिंता का विषय है क्योंकि आज की पीढ़ी जिस प्रकार से एक-दूसरे के साथ पेश आ रही है वह देश हित में तो नहीं है।

न्याय व्यवस्था में जमानत और गरीबी का सवाल

सामायिक
अमरपाल सिंह वर्मा
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल में उम्रकैद की सजा भुगत रहे एक कैदी खरताराम की चिट्ठी को ही याचिका मानकर सुनाए गए फैसले में कहा है कि गरीबी कोई अपराध नहीं है और न ही यह किसी व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित करने का आधार बन सकती है। पाली जिले का निवासी खरताराम हत्या के एक मामले में 2014 से सजा काट रहा है। जिला पैरोल कमेटी ने 29 सितंबर 2025 को उसे चौथी बार 40 दिन की नियमित पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया लेकिन इसके साथ 25-25 हजार रुपए के दो जमानती पेश करने की शर्त जोड़ दी गई। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर होने के कारण खरताराम यह शर्त पूरी नहीं कर सका। उसके पास वकील करने तक के पैसे नहीं थे, इसलिए उसने जेल से ही पोस्टकार्ड भेजकर हाईकोर्ट से गुहार लगाई। हाईकोर्ट ने न केवल उसकी याचिका सुनी बल्कि इस फैसले को ऐसे मामलों में एक नजीर के रूप में स्थापित कर दिया। अदालत ने स्पष्ट कहा कि पैरोल या जमानत की शर्तें तय करते समय अधिकारियों को मशीनी रवैया छोड़कर मानवीय और संवैधानिक दृष्टि अपनानी होगी।

यह फैसला केवल एक कैदी को राहत देने तक सीमित नहीं है बल्कि यह उस व्यापक समस्या की ओर इशारा करता है, जिसमें देश में हजारों गरीब कैदी फंसे हुए हैं। सवाल केवल पैरोल का नहीं है। सवाल उस व्यापक ढांचे का है, जहां जमानत, पैरोल और अर्थदंड जैसे कानूनी प्रावधान गरीब व्यक्ति के लिए राहत नहीं बल्कि नई सजा बन जाते हैं। देश की जेलों में आज भी बड़ी संख्या में ऐसे कैदी बंद हैं जिन्हें अदालतें जमानत या पैरोल दे चुकी हैं लेकिन पैसे के अभाव में वे सलाखों के पीछे ही पड़े हैं। कई ऐसे भी हैं जिनकी सजा की अवधि पूरी हो चुकी है मगर जुर्माना भरने में असमर्थ होने के कारण उन्हें रिहाई नहीं मिल पा रही। इस तरह कानून की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद भी कैद केवल इसलिए जारी रहती है क्योंकि वह व्यक्ति गरीब है। इसका सबसे सीधा असर जेलों पर पड़ता है। जेलें अपनी निर्धारित क्षमता से कहीं अधिक भरी हुई हैं। विचाराधीन बंदियों की संख्या बहुत बड़ी है। जेलों में भीड़ के कारण कम जगह तथा सीमित संसाधनों का परिणाम खराब स्वास्थ्य सुविधाओं के रूप में निकलता है। जेलों में अपराधियों को रखने के पीछे सुधार का मूल उद्देश्य भटक चुका है।

यह समस्या कितनी गंभीर है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 26 नवंबर 2022 को संविधान दिवस के अवसर पर स्वयं राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को कहना पड़ा कि देश की जेलों में हजारों ऐसे कैदी बंद हैं जिनके पास

जमानत पर रिहाई का कोर्ट आदेश तो है लेकिन जमानत राशि के पैसे नहीं हैं। उन्होंने अदालतों और सरकार से इन कैदियों के लिए समाधान निकालने की अपील की थी। राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के दो दिन बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए केंद्र और राज्यों से रिपोर्ट तलब कर ली। इसके बाद फरवरी 2023 में सर्वोच्च अदालत ने इस मुद्दे पर सात महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। अदालत की मंशा साफ है कि जमानत आदेश की सार्थकता तभी है, जब वह वास्तव में किसी को जेल से बाहर ला सके।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश एक रिपोर्ट में सामने आया कि जनवरी 2023 तक 5,380 ऐसे कैदी थे, जिन्हें जमानत मिल चुकी थी लेकिन वे अब भी जेलों में बंद थे। सबके मामलों में कारण पैसे का अभाव का ही था। 2023 में ही सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल अदालतों को निर्देश दिए कि वे जमानत की शर्तें तय करते समय कैदियों की आर्थिक स्थिति पर भी विचार करें। अदालत ने साफ शब्दों में कहा कि अगर जमानत की शर्तें कैदी की हैसियत से परे हैं तो ऐसी जमानत का कोई अर्थ नहीं रह जाता। राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला भी इसी सोच की अगली कड़ी है। सुप्रीम कोर्ट की इसी संवैधानिक सोच का अनुसरण करते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने अब यह महत्वपूर्ण फैसला दिया है। इसमें हाईकोर्ट ने माना है कि पैरोल एक सुधारात्मक अधिकार है, यह अमीरों का विशेषाधिकार नहीं है।

कोर्ट ने अधिकारियों की उस प्रवृत्ति पर कड़ी नाराजगी जताई है, जिसमें हर मामले में एक जैसी जमानत शर्तें थोप दी जाती हैं। यह भी नहीं देखा जाता है कि कैदी उन्हें पूरा करने की स्थिति में है या नहीं। हाई कोर्ट द्वारा जारी की गई छह सूत्रीय गाइडलाइन से इस बात का संकेत मिलता है कि अदालतें अब केवल आदेश देने तक सीमित नहीं रहना चाहतीं, बल्कि उसके प्रभावी क्रियान्वयन पर भी बल देना चाहती हैं। अदालतें बार-बार निर्देश दे रही हैं लेकिन बड़ा सवाल है कि नीतियों और आदेशों का धरातलीय क्रियान्वयन क्यों नहीं हो पा रहा है? सुप्रीम कोर्ट पहले ही अनावश्यक गिरफ्तारी, रिमांड और जमानत के बावजूद जेल में बंद रखने की प्रवृत्ति पर नाराजगी जता चुका है। कोर्ट ने गरीब कैदियों की मदद के लिए एक मानक प्रक्रिया और फंड की व्यवस्था की बात भी कही है लेकिन अधिकांश राज्यों में यह पहल धरातल पर पहुंचने का इंतजार है। हाल में हरियाणा सरकार ने फैसला किया है कि वह गरीब कैदियों को जमानत या जुर्माना भरने में आर्थिक सहायता देगी। जमानत के लिए एक लाख रुपये तक और जुर्माने के लिए 25 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। यह एक सकारात्मक कदम है जिसे अपवाद नहीं बल्कि नियम बनाया जाना चाहिए। सभी राज्यों को ऐसी योजनाएं लागू करनी होंगी। जमानत और पैरोल की शर्तें तय करते समय आर्थिक स्थिति का वास्तविक आकलन होना चाहिए। जिला स्तर पर ऐसे तंत्र विकसित करने की जरूरत है, जो यह सुनिश्चित करें कि किसी व्यक्ति को केवल गरीबी के कारण जेल में न रहना पड़े। गरीब कैदी अपनी बात अदालत तक पहुंचा सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी सहायता सेवाओं को मजबूत करना होगा क्योंकि जरूरी नहीं कि हर जज किसी कैदी के पोस्टकार्ड को याचिका मान ही ले। जेलों को दंड के नहीं बल्कि सुधार के स्थान के रूप में देखने की सोच विकसित की जरूरत है। ऐसा होने पर ही अदालती फैसलों को सही मायने में कियान्वित किया जा सकेगा। समाधान साफ हैं, बस इच्छाशक्ति की जरूरत है।

चाइनीज मांझे की डोर, मौत की ओर

मुद्दा
सपना सी.पी. साहू 'स्वप्निल'

मकर संक्रांति सूर्य के उत्तरायण होने का वह पावन पर्व है, जो भारतीय संस्कृति में दान-पुण्य, तिल-गुड़ की मिठास और नई ऊर्जा का संचार लेकर आता है। आकाश में डोलती रंग-बिरंगी पतंगें मनुष्य की ऊंची आकांक्षाओं और उमंगों का प्रतीक हैं। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, इस उत्सव की मिठास पर चाइनीज मांझे का घातक जहर घुल गया है। जिसे हम शौकिया तौर पर आकाश में उड़ाते हैं, वह जमीन पर किसी निर्दोष राहगीर के लिए फंदा बन जाता है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के वाराणसी और मेरठ और मध्यप्रदेश के इंदौर जैसे जीवंत शहर में हाल ही में हुई हृदयविदारक घटना, जहां मौत के मांझे में लिपटी चाइनीज डोर एक युवक का गला काट गई और कई घायल हुए। इस बात का प्रमाण हैं कि प्रशासन की पाबंदी और हमारी नागरिक जागरूकता के बीच एक बहुत बड़ी गहरी और जानलेवा खाई अभी भी है।

चाइनीज डोर से सैकड़ों मौत के केस गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि जैसे राज्यों से सामने आ रहे है। हर वर्ष पतंगबाजों को समझाइश दी जा रही है। इतने साहित्यिक आलेखों, विज्ञापनों आदि के माध्यम से खूनी चाइनीज मांझे से बचाव की अपील की जा रही है पर दुखद घटनाएं तो जैसे खत्म ही नहीं हो रही। साधारण बोलचाल की भाषा में जिसे हम चाइनीज मांझा कहते हैं, उसका चीन से अब कोई सीधा संबंध नहीं रह गया है। यह हमारे अपने ही बाजारों में बिकने वाला एक घातक उत्पाद है। यह वास्तव में हमारे भारत में ही प्लास्टिक, नायलॉन या सिंथेटिक धागों से बना जानलेवा धागा होता है, जिस पर बारीक पिसे हुए कांच और लोहे के चूरे की परत चढ़ाई जाती है। वैज्ञानिक भाषा में इसे मोनोफिलामेंट स्ट्रिंग कहा जाता है। इसकी भयावहता सीधे जानलेवा दुर्घटना है, इसके मुख्य कारण है कि यह अटूट और धारदार डोर है। पारंपरिक सूती मांझा हाथ या झटके से टूट जाता है, लेकिन नायलॉन का यह धागा इतना मजबूत होता है कि यह इंसान की हड्डी, मांस और धमनियों को सर्जिकल ब्लेड की तरह चीर देता है।

यह धागा विद्युत सुचालक होता है। इसमें धातु के अंश होने के कारण, जब यह बिजली के हाई-टेंशन तारों के संपर्क में आता है, तो पतंग उड़ाने वाले को जानलेवा करंट लगने का भी डर रहता है। यह चाइनीज धागा पर्यावरण का दुश्मन भी है। यह अजैव निम्नीकरणीय (नॉन-बायोडिग्रेडेबल) है। इसमें प्लास्टिक और कांच का समायोजन होता है, यानी यह कभी नष्ट नहीं होगा। हम साधारणतया देखते है कि उत्सव खत्म होने के महीनों बाद भी यह पेड़ों, खंभों और छतों पर फंसा रह जाता है। इसकी चपेट में आने से कई बेजुबान पशु-पक्षी को भी नुकसान पहुंचता है। यह पक्षियों के पैरों और पंखों को काटकर उन्हें तड़प-तड़प कर मरने पर मजबूर कर देती है।

चाइनीज डोर बेचना मौत का कारोबार करने जैसा है। जिसमें चंद रुपयों का लालच किसी के घर के चिराग बुझा देता है। प्रश्न उठता है कि जब यह प्रतिबंधित है, तो बाजारों में कैसे पहुंच रहा है? असल में, यह मौत का कारोबार लोभ पर टिका है। कुछ दुकानदार अधिक मुनाफे के लिए इसे गुप्त ठिकानों से बेच रहे हैं। कानूनी तौर पर, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने देशभर में नायलॉन या सिंथेटिक मांझे के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के तहत इस पर भारी जुर्माना और जेल का प्रावधान है। इंदौर, गुजरात, उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रशासन भी लगातार छापे मार रहे हैं, लेकिन जब तक उपभोक्ता खुद ही इसकी मांग करना बंद नहीं करेगा, तब तक यह कालाबाजारी रुकना लगभग असंभव है।

इस समस्या के समाधान हेतु सामुदायिक निगरानी एक सशक्त विकल्प हो सकता है। स्थानीय मोहल्ला समितियों और युवा मंडलों को सक्रिय होकर अपने क्षेत्रों में निगरानी रखनी चाहिए। यदि कहीं भी इस प्रतिबंधित डोर का उपयोग या बिक्री दिखे, तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को देनी चाहिए। सामूहिक बहिष्कार ही इस जानलेवा डोर की जड़ काट सकता है।

बढ़ती दुखद घटनाओं को देखते हुए सुरक्षित रहने के लिए निम्नलिखित जीवन रक्षक उपाय अपनाना अनिवार्य है:-

दोपहिया चलाते समय गले को कवच दें। मफलर, मोटा स्कार्फ, लेदर या ऊन का गले पर मोटा कपड़ा (नेक गार्ड) जरूर पहनें। हेलमेट का वाइजर (शीशा) हमेशा नीचे रखें ताकि मांझा आपकी आंखों या चेहरे को नुकसान न पहुंचा सके। पतंगबाजी वाले इलाकों या फ्लाईओवर पर वाहन की गति अत्यंत धीमी रखें। अपनी मोटरसाइकिल या एक्टिवा के आगे लोहे का सुरक्षा वायर (यू-गार्ड) लगवाएं। परंतु पतंगबाजों का नैतिक उत्तरदायित्व, सुरक्षा रखने वालों से अधिक बनता है। उनको अपने शौक के लिए केवल स्वदेशी पारंपरिक सूती धागे का उपयोग करना चाहिए। उत्सव की गरिमा सादगी और प्रेम में है, किसी को क्षति पहुंचाने में नहीं। पतंगबाजों को मन में दया का भाव बढ़ाना चाहिए। सुबह और शाम के समय (जब पक्षी घोंसलों से निकलते या लौटते हैं) पतंगबाजी न करें।

हमें समझना होगा और समझाना होगा कि पतंग की डोर हमारे हाथ में होनी चाहिए, न कि हमारा विवेक उस डोर के हाथों बिक जाए। पर्व-त्योहार खुशियां बांटने के लिए होते हैं, शोक मनाने के लिए नहीं। इस संक्रांति पर आइए हम सभी संकल्प लें कि हम न केवल स्वयं चाइनीज मांझे का पूर्ण बहिष्कार करेंगे, बल्कि दूसरों को भी जागरूक करेंगे। आसमान की ऊंचाई तब तक ही सुंदर और सार्थक है, जब तक जमीन पर रहने वाला हर इंसान, प्राणी और परिंदा सुरक्षित है। तिल-गुड़ की मिठास के साथ सुरक्षा का संकल्प ही इस पर्व की सच्ची दानशीलता होगी।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

अगर किताब उबाऊ निकल जाए तो पाठक किस को धकियाए?

व्यंग्य
अतुल चतुर्वेदी
लेखक व्यंग्यकार हैं।

धुँध सब तरफ़ छायी है इन दिनों, उन्होंने दुखी होते हुए कहा। क्या साहित्य, क्या राजनीति और क्या समाज में। मैंने कहा आजकल ऐसे ही दिन है भाईसाहब जिससेउम्मीद होती है कि यह कुछ उजाला लाएगा वही अगले पल स्वयं ही किसी कोहरे मेंघिरा पाया जाता है। वे और दुखी हो गये कहने लगे, देखा नहीं आपने वरिष्ठ रचनाकारों की कोई पूछ ही नहीं है उनके लिखे को कोई रेखांकित ही नहीं कर रहा है। क्या साहित्य में भी मार्गदर्शक मण्डल की स्थापना होगी? मैंने कहा नये लोगों को मौक़ा दिया जा रहा है इसमें बुराई क्या है? वो बोले घर के पुराने बर्तन फेंक देते हो क्या? विरासत भी कोई मूल्य रखती है, जड़ों के बिना शाखाओं का क्या अस्तित्व? मैं उनके तर्क के आगे अधिकतर चुप हो जाता हूँ। वे वैसे ही धुँध से दुखी हैं मैं उनकोऔर दुखी नहीं करना चाहता। वे बोले देखो, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा है ...पता नहीं कौन किस को किधर लिए जा रहा है। मैंने कहा कह तो सब यही रहे हैं किहमारे साथ चलो, हमारा रास्ता विकास और कल्याण का रास्ता है। अब यह तो जनता पर है कि वो किस राह को पकड़ती है।

वो बोले राहों का क्या है वहाँ तो राहजन भीबैठे हैं चेहरे पर नक़ाब डाले। सवाल तो यह है कि ऐसे घने कोहरे में जब गाड़ियाँ चढ़ी जा रही हैं एक दूसरे पर पाठकों का क्या है वो तो तुरंत भटक सकता है। कोई भी कमजोर रचना उसका संस्कार और आस्वादन बिगाड़ सकती है। मेरी चिंता में देशऔर आम नागरिक था उनकी चिंता में साहित्य और पाठक। वैसे अंतर कोई विशेष नहीं था हम दोनों ही एक सड़क के दो छोरों पर चिंतारत थे बस फ़ासला बीच की सड़क का था। इसे आप सोच का फ़ासला भी कह सकते हैं। उस पार सड़क केदिख मुझे भी कुछ नहीं रहा था और उन्हें भी कुछ नहीं। वो क़रीब आ कर बोले, देखा यह भ्रम की धुँध कुछ भी निर्णय नहीं लेने दे रही। आदमी जाए तो जाए कहाँ। किस की राह का अनुसरण करे, कहीं कोई भटका कर अभयारण्य में ले गया तो देश तो गया न दशकों पीछे। और देश गया तो साहित्य भी। मैंने कहा साहित्य तो आगे चलने वाली मशाल है प्रेमचंद ने कहा था। बोले उस मशाल में स्वाभिमान का ईंधनथा इस टॉर्च में चाटुकारिता और जुगाड़ के सेल लगे है चलने की कोई गारंटी नहीं।अंधेरा फिर बरकरार रह सकता है और गंतव्य फिर धुंधला सकता है।

टकराहट फिर बढ़ सकती है जब जगह कम होती है मंच पर और दावेदार ज़्यादा तो अक्सर या तो आकांक्षाओं के बोझ से मंच टूट जाते हैं या भगदड़ में सूझ नहीं पाता कि जाना किस के साथ और निकल किस के साथआए। आने वाले दिनों में अनिश्चय की ओस और गिरेगी, अविश्वास का कोहराऔर बढ़ेगा। आरोप प्रत्यारोप का शोर चरम पर होगा। साहित्य लोकप्रियता की फुटपाथ पर खड़ा ठिठुर रहा होगा। शब्द अभिव्यक्ति के सुरक्षित मार्ग ढूँढ रहे होंगे, पाठक पहचान ज़ाहिर न करने की शर्त पर प्रतिक्रिया देने को तैयार होंगे। रचना तो अच्छी थी लेकिन संदेश स्पष्ट नहीं है कि लेखक क्या कहना चाहता है।

अब लेखक तो तब कुछ कहे जब उसे कुछ दिखे और जो दिखे उसे समझने और सुनने, माननेवाले हों। इस कोहरे में संपूर्ण परिदृश्य ही गड्ड मद्द है। कलाएँ हाशिए पर हैं औरभड़ैती चरम पर। सच्चा लेखक हाँफ़ रहा है और फ़र्ज़ी हर मंच पर हांक रहा है। यूट्यूबर नोट छाप रहे हैं, ब्लॉगर बगले झांक रहे हैं। वत्स यह विस्थापन का दौर है यहाँ पुकार अट्टहास से और ईमानदारी टुटकों से धकियाई जा रही है और आप हैं कि इस कोलाहल में रास्ता खोज रहे हैं। गीत रैप हुए जा रहे हैं, व्यंग्य वन लाइनर में जा कर छरहरा हो गया है। कथाओं के अकाल के चलते कथेतर गद्य की खेती लहला रही है। धुंध कुछ इस कदर छायी है कि व्यंग्य ढूँढने निकलो तो राजनीतिक दल का बयान निकलता है और कविता तलाशो तो गद्यात्मक बयानबाज़ी। फिर भी सब साथी हाथ बढ़ाना रे की तर्ज़ पर एक दूसरे को धकिया रहे हैं। आलोचक प्रकाशक को, प्रकाशक लेखक को और लेखक पाठक को भैया मेरी किताब पढ़ो। अगर किताब उबाऊ निकल जाए तो पाठक किस को धकियाए उस हाशिए पर खड़े आदमी पर क्या रास्ता है बच निकलने का। ऐसी गफ़लत में वो किधर का रास्ता संभालेगा? किताबों से मोहभंग का या लेखक बन बदला निकालने का? इस कठिन और भ्रमपूर्ण समय में यह पता लगाना भी किसी चुनौती से कम नहीं है।

डिजिटल क्रांति

डॉ. सुधीर कुमार

(कुरुक्षेत्र विवि के विधि विभाग में सहायक प्रोफेसर)

कलम और कोडिंग के बीच छिड़ा कला का कुरुक्षेत्र

आज की डिजिटल क्रांति के दौर में जब हम सुबह उठते हैं, तो संभव है कि सोशल मीडिया पर दिखी कोई मंत्रमुग्ध कर देने वाली पेंटिंग या कानों में रस घोलता कोई नया संगीत किसी इंसान ने नहीं, बल्कि एक 'ब्लैक बॉक्स' यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने बनाया हो। मिड जर्नी और चैट जीपीटी जैसे टूल्स ने सृजन की सदियों पुरानी परिभाषा को चुनौती दी है। लेकिन, इस तकनीकी छलांग के साथ ही एक वैश्विक कानूनी युद्ध शुरू हो गया कि क्या एक मशीन 'कलाकार' हो सकती है? और यदि हाँ, तो उस कला का असली मालिक कौन है। कोडिंग करने वाला इंजीनियर, डेटा देने वाला कलाकार, या स्वयं मशीन! कल्पना कीजिए, एक सॉफ्टवेयर लाखों पेंटिंग्स को स्कैन करता है, पिकासो के ब्रश स्ट्रोक्स को समझता है, दा विंची के रंगों के संयोजन को सीखता है और पलक झपकते ही एक ऐसी तस्वीर बना देता है जो बिल्कुल मौलिक लगती है। इसे 'जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस' कहते हैं।

भारतीय संदर्भ में देखें तो हमारी संस्कृति 'साधना' और 'मानवीय संवेदना' की रही है। जब एक एल्गोरिदम बिना किसी रूह या एहसास के 'कला' पैदा करता है, तो सवाल उठता है कि क्या केवल डेटा की प्रोसेसिंग को 'सृजन' माना जा सकता है? आलोचकों का तर्क है कि एआई कुछ नया नहीं बनाता, बल्कि वह इंटरनेट पर मौजूद करोड़ों कलाकारों की मेहनत को 'रीमिक्स' करता है। इसे 'डिजिटल चोरी' कहें या 'नया आविष्कार', यही आज की सबसे बड़ी कानूनी और नैतिक बहस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कॉपिराइट की इस बहस में अमेरिका का 'थेलर बनाम पेल्मटर' केस एक मील का पत्थर बन गया है। स्टीफन थेलर नामक एक कंप्यूटर वैज्ञानिक ने अपनी एआई मशीन 'क्रिएटीविटी मशीन' द्वारा बनाई गई एक कलाकृति 'अ रीसेंट एंट्रेंस टू पैराडाइज' के लिए कॉपीराइट आवेदन किया।

थेलर का तर्क था कि चूंकि मशीन ने इसे स्वायत्त रूप से बनाया है, इसलिए मशीन को ही लेखक माना जाए। अगस्त 2023 में अमेरिकी जिला अदालत की न्यायाधीश बेरिल पेल्मटर ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए थेलर की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मानवीय भागीदारी कॉपीराइट की एक अनिवार्य शर्त है। अदालत ने सदियों पुराने कानूनों का हवाला देते हुए कहा कि कॉपीराइट केवल इंसानों की बौद्धिक संपदा की रक्षा के लिए बना है, मशीनों के लिए नहीं। यह फैसला दुनिया भर के देशों के लिए एक नजीर बन गया है कि बिना मानवीय स्पर्श के किसी भी सृजन को कानूनी संरक्षण नहीं मिल सकता।

भारत में कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 2(d) के अनुसार, किसी भी कार्य का रचयिता वह 'व्यक्ति' है जो उसे बनाता है। यहाँ 'व्यक्ति' शब्द का कानूनी अर्थ हमेशा एक 'प्राकृतिक इंसान' से लिया गया है। हाल ही में भारत में 'राघव' नामक एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐप को लेकर विवाद हुआ था। शुरुआत में इसे एक कलाकृति के 'सह-लेखक' के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति मिल गई थी, लेकिन जब मामला गहराया, तो कॉपीराइट कार्यालय ने इसे कानूनी पेचीदगियों के कारण वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। भारत की संसद की एक स्थायी समिति ने भी सुझाव दिया है कि मौजूदा कानूनों में बदलाव की जरूरत है ताकि एआई द्वारा बनाई गई रचनाओं को उचित श्रेणी में रखा जा सके, लेकिन प्राथमिकता हमेशा मानव कलाकार को ही मिलनी चाहिए।

वर्तमान डिजिटल युग में 'डेटा स्क्रैपिंग' बौद्धिक संपदा के लिए सबसे बड़ा खतरा बनकर उभरी है। एआई कंपनियां अपने मॉडल्स को प्रशिक्षित करने के लिए इंटरनेट पर मौजूद दुनिया भर के कलाकारों की पेंटिंग और लेखकों की कालजयी कृतियों को बिना किसी अनुमति के खंगाल रही हैं। इसे तकनीकी भाषा में भले ही 'लर्निंग' या 'ट्रेनिंग' कहा जाए, लेकिन मौलिक रचनाकारों के लिए यह उनकी मेहनत की अनधिकृत कटाई जैसा है। हाल ही में 'न्यूयॉर्क टाइम्स बनाम ओपन एआई' का कानूनी संघर्ष इसी वैचारिक युद्ध का प्रतीक बन गया है, जहाँ एक प्रतिष्ठित समाचार संस्थान ने अपनी बौद्धिक संपदा के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए करोड़ों लेखों के अवैध इस्तेमाल को चुनौती दी है।

संकट केवल डेटा के उपयोग तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पहचान की चोरी तक जा पहुँचा है। आज वॉटरमार्क और हस्ताक्षर का महत्व कम होता जा रहा है क्योंकि एआई किसी भी कलाकार की विशिष्ट शैली की इतनी बारीकी से नकल कर लेता है कि असली और मशीनी सृजन के बीच का भेद लगभग समाप्त हो गया है। जब एक मशीन किसी पेंटर की बरसों की साधना को चंद सेकंड के 'प्रॉम्प्ट' में दोहरा देती है, तो वह केवल एक उपकरण नहीं रह जाती, बल्कि कला के अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती बन जाती है। यदि कानूनी ढांचे में जल्द ही बदलाव नहीं किए गए, तो 'आधुनिक उपकरण' के नाम पर 'डिजिटल चोरी' का यह सिलसिला रचनात्मक जगत की नींव हिला देगा।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कलाकारों की जगह लेने के बजाय उनके काम को आसान बनाने का एक औजार है। यह उन जटिल और दोहराव वाले कार्यों को चंद सेकंडों में पूरा कर सकता है जिनमें पहले घंटों का समय बर्बाद होता था। इससे कलाकारों को यह स्वतंत्रता मिलती है कि वे बारीक तकनीकी प्रक्रियाओं के बजाय गहरे, मौलिक और अधिक रचनात्मक विचारों पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकें। इसके अलावा, तकनीक का यह विकास रोजगार के नए द्वार भी खोल रहा है। 'प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग' जैसे उभरते क्षेत्र इस बात का प्रमाण हैं कि भविष्य में उन विशेषज्ञों की भारी मांग होगी जो मशीन और मानव मस्तिष्क के बीच सेतु बनकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सही दिशा दे सकें। अंततः, कला केवल तकनीक से नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं से जीवंत होती है; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस संवेदना को आकार देने वाला एक आधुनिक कैनवास मात्र है। सृजन के इस नए और चुनौतीपूर्ण युग में कानून और तकनीक के बीच सामंजस्य बिठाना अब ऐच्छिक नहीं, बल्कि अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सबसे पहला कदम एट्रिब्यूशन और रॉयल्टी की एक पारदर्शी व्यवस्था विकसित करना है। यदि कोई एआई मॉडल किसी जीवित कलाकार के काम और डेटा से प्रशिक्षित होकर नई सामग्री सृजित कर रहा है, तो उस मूल कलाकार को उसका उचित 'क्रेडिट' और आर्थिक लाभ मिलना ही चाहिए। यह न केवल कलाकार के श्रम का सम्मान होगा, बल्कि कला की मौलिकता को भी जीवित रखेगा।

साथ ही, सूचना की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए सरकार को अनिवार्य प्रकटीकरण के कड़े नियम बनाने होंगे। प्रत्येक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनित सामग्री पर एक विशिष्ट 'टैग' या 'डिजिटल वॉटरमार्क' होना चाहिए, जिससे उपभोक्ता स्पष्ट रूप से पहचान सकें कि सामग्री मशीन द्वारा निर्मित है न कि मानव द्वारा। अंततः, हमें एक ऐसे संशोधित कॉपीराइट ढांचे की आवश्यकता है जो 'हाइब्रिड मॉडल' पर आधारित हो। इस ढांचे के भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को केवल एक 'रचनात्मक उपकरण' माना जाना चाहिए, जिसका मालिकाना हक उस व्यक्ति के पास हो जिसने अपने विशिष्ट निर्देशों और कल्पना से उस मशीन को दिशा दी है। इस तरह के संतुलित कानूनी सुधार ही भविष्य के डिजिटल परिदृश्य में क्रिएटर्स के अधिकारों को सुरक्षित रख पाएंगे।

बिना रूह का कलाकार केवल डेटा प्रोसेस कर सकता है, वह 'अनुभव' और 'पीड़ा' को शब्द नहीं दे सकता। एक माँ की ममता, विरह का दुख या देशभक्ति का जज्बा वही लिख सकता है जिसने उसे जीया हो। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बेहतरीन 'पेंट ब्रश' हो सकता है, लेकिन उसे पकड़ने वाला हाथ हमेशा इंसान का ही होना चाहिए। सृजन का श्रेय उस मशीन को नहीं, बल्कि उस मानवीय मेधा को मिलना चाहिए जिसने उस मशीन को बनाया और उसी दिशा दी। हमें तकनीक से डरने की बजाय उसे कानून के दायरे में बांधने की जरूरत है, ताकि 'पिकासो' की विरासत भी सुरक्षित रहे और भविष्य का 'एल्गोरिदम' भी मानवता के काम आ सके। कला बदलती है, समाप्त नहीं होती।

राजनीति

राजीव खंडेलवाल

लेखक, कर सलाहकार हैं।

क्या 'सोरेन' या 'केजरीवाल' बनने जा रही हैं ममता?

8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े चुनावी रणनीतिकार संगठन ''आई-पैक'' (इंडियन पॉलीटिकल एक्शन कमेटी) के कोलकाता स्थित कार्यालय, निदेशक एवं सह-संस्थापक प्रतीक जैन (संस्थापक प्रशांत किशोर) के आवास सहित कुल 10 परिसरों (जिनमें दिल्ली के 4 परिसर भी शामिल हैं) पर एक साथ छापेमारी की गई।

क्या मात्र इस आधार पर कि आरोपित कंपनी किसी राजनीतिक दल के लिए ''सलाहकार कंपनी'' के रूप में काम कर रही थी, पर पड़े छापे को ''राजनीतिक प्रतिशोध की संज्ञा'' दी सकती है? जबकि वास्तव में यह कार्रवाई तथाकथित 1352 करोड़ रुपये के कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े प्रतीक जैन के लगभग 10-12 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई बतलाई जाती है। जवाब में ममता ने अमित शाह के विरूद्ध तथाकथित कोयला घोटाले के जहां जबकि वे छापे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री से अमित शाह को नियंत्रण में रखने की बात कह रही थी। पैसे लेने के सबूत की कथित पेन ड्राइव होने के बावजूद जारी न करना ममता के ''तेवर'' से मेल नहीं खाता है। इसका साफ मतलब पेन ड्राइव की ''वास्तविकता'' ही कोसो दूर है। अचानक पड़े ईडी के छापे के दौरान पश्चिम बंगाल की शेरनी कही जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ छापा स्थलों पर जिस तत्परता से पहुंचकर वहां से एक 'हरी फाइल', हार्डडिस्क, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज ''जबरन'' अपने साथ ले गईं। गोया कि ''तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ ..... ''।

''घटना का परिणाम?''

हाल के वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दो अलग-अलग राजनीतिक परिणाम देश देख चुका है। एक, अरविंद केजरीवाल के विरूद्ध विधानसभा चुनाव से लगभग 65 दिन पूर्व कार्रवाई, गिरफ्तारी, जेल से शासन चलाने का केजरीवाल का ''हथेली पर सरसों जमाने जैसा'' अभूतपूर्व, दुस्साहसिक एवं अनैतिक प्रयोग।

दूसरा हेमंत सोरेन के विरूद्ध चुनाव से लगभग 290 दिन पूर्व कार्रवाई, परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा। स्पष्ट है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में ममता के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है। तब ममता बनर्जी-कौन-सा रास्ता चुनेगी?

''राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और न्यायिक मोर्चा।''

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को टीएमसी के ''आई.टी. सेल'' का प्रमुख बतलाते हुए ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया। वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा ''जबरन'' दस्तावेज हटाना जांच में ''बाधा'' है। इसी आधार पर ईडी ने कोलकाता उच्च न्यायालय का रुख किया। दूसरी ओर, टीएमसी ने भी छापेमारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। प्रतीक जैन के परिजनों ने भी ईडी की छापा कार्रवाई के दौरान कीमती सामान की चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है।

जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस घटना के भी स्पष्ट रूप से निम्न दो पहलू है। टीएमसी जहां इसे बीजेपी-नीति केंद्र द्वारा लक्षित उत्पीड़न के रूप में देख रही है, वहीं अन्य इसे वित्तीय अनियमितताओं की वैध जांच के रूप में देखते हैं। पूरा घटनाक्रम देश में एक बड़े राजनीतिक, संवैधानिक मर्यादा, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन का विवाद का रूप ले चुका है। इस पर राजनीतिक जोड़-घटाना किए बिना गंभीरता से मनन किया जाने की अत्यंत आवश्यकता है।

स्वतंत्र भारत के इतिहास की संभवतः यह पहली ऐसी अवांछित घटना है, जहां किसी राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंचकर दस्तावेज ले जाकर जांच में बाधा डालते दिखाई दी हों, और जांच एजेंसी को ''अरध तजहिं बुध सरबस जाता'' की तर्ज पर ''आंसू पीकर बेबस रह जाना'' पड़ा हो।

यह घटना ''भारत संघ'' जो ''राज्यों के संघ'' से मिलकर बना है, की 'अनेकता में एकता' की भावना पर गहरा आघात होकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है। यह केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी संकट का संकेत भी है। जिससे ''पार पाना तलवार की धार पर चलने जैसा'' है।

ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर आसीन हैं। ईडी की कार्रवाई में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व बाधा निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। यदि ममता को आशंका थी कि ईडी के माध्यम से भाजपा द्वारा तथाकथित दस्तावेजों का दुरुपयोग होगा, तो संवैधानिक मर्यादा की रक्षा हेतु या तो वे पद से मुक्त होकर उक्त कार्य करती अथवा ''गांधारी'' होकर ''दुर्योधन'' को उक्त दस्तावेज लाने भेजती, ताकि संवैधानिक मुख्यमंत्री पद की मर्यादा बनी रहती। तथापि सड़क पर संघर्ष कर विरोध प्रकट करना ममता का संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है।

1956 में प्रवर्तन निदेशालय की स्थापना हुई, किंतु मनी लॉन्ड्रिंग निवारण अधिनियम (पीएमएलए) 2002 और संशोधित अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद से वर्ष 2014 से इसके प्रयोग में तीव्रता आई। तब से ''सीबीआई'' से ज्यादा ''खौफ'' ''ईडी'' का हो गया है। यह सीबीआई वही है, जिसे गैर भाजपा शासित 11 राज्यों की सरकारों ने भिन्न-भिन्न समयों पर अपने-अपने प्रदेशों में प्रवेश पर रोक लगा दी थी। यही नहीं, इसी सीबीआई के बावत उच्चतम न्यायालय ने ''यूपीए'' (2013 में) से लेकर ''एनडीए'' (2024 में) सरकार तक में उसे ''पिंजरे का तोता'' कह दिया था, यानी कि ''लोग मशहूर हो गए इन्हें शर्मसार करते करते''। तब जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर प्रश्न उठना स्वाभाविक ही है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कई बार डंडा चलाये जाने के बावजूद केंद्रीय एजेंसियो की कार्य कुशलता में अपेक्षित सुधार न होने, और ''दर्द का हद से गुजरना है दवा हो जाना'' वाली स्थिति में क्या भविष्य में विपक्ष को ममता बनर्जी जैसे कदम उठाकर जांच एजेंसियों का सामना करना होगा? जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण होगा?

यह उल्लेखनीय है कि 2015 से अब तक 5892 मामलों में केवल 15 दोषसिद्धियाँ हुई हैं। अगस्त 2025 में उच्चतम न्यायालय ने ईडी की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे ''crook अर्थात् धोखेबाज अपराधी जैसे व्यवहार' से बाज आने की चेतावनी इस आधार पर दी थी कि 2015 से अब तक ''पीएमएलए'' के तहत 5892 मामलों में केवल 15 दो दोष सिद्धियां अर्थात् मात्र 0.5% हुई थी। 2014-2024 के बीच हुए 7264 छापों में केवल 3% मामले राजनेताओं से जुड़े हैं, जिनमें लगभग 98% विपक्षी दलों से संबंधित हैं।

यहां सवाल ईडी के ''अधिकार'' या ''क्षेत्राधिकार'' का नहीं, बल्कि अधिकार के उपयोग उर्फ ''अलादीन के चिराग में से जिन्न को बाहर निकालने'' के ''समय'' को लेकर है, जो ''अनुत्तरित'' है। वर्ष 2020 में दर्ज प्राथमिकी पर पाँच वर्षों तक कोई कार्रवाई नहीं? और चुनाव से मात्र तीन महीने पहले सो कर उठकर ''आकाश पाताल एक करने की'' आवश्यकता क्यों? तथा छापेमारी चुनाव के तीन महीनों बाद करने पर क्या ''कारवां गुजर चुका होगा''?

'क्या यह महज संयोग है या प्रयोग?

यह तर्क कि 'देश में कहीं न कहीं चुनाव चलते ही रहते हैं' ''आंख में धूल झोंकने वाला है''। यह एक तकनीकी बहाना मात्र है। यह तो ''नानी के आगे ननिहाल की बात करने जैसा'' है। क्योंकि व्यवहार में छापे प्रायः विपक्ष-शासित राज्यों में, नेताओं पर ही है अथवा भाजपा शासित राज्यों में विपक्षी नेताओं पर ही देखे गए हैं। ''कानून अपना काम कर रहा है'', यह एक ''तकिया कलाम'' बन गया है। यह भी कहा जाता है, यदि आप ईमानदार है, तो छापे से क्यों डर रहे हैं? ये सब ''तकनीकी बातें सुनने में अच्छी है। परन्तु शाब्दिक अर्थ व यथार्थ'' (धरातल की वास्तविकता) में कितना गैप (अंतर) है? यह अंतर ही ईडी के आशय, दुराशय, सदाशय पर प्रश्न पैदा कर रहा है। ''दामन पे कोई छींट ना खंजर पे कोई दाग, तुम कत्ल करो हो कि करामात करो हो''।

प्रश्न यह नहीं कि जांच हो रही है, बल्कि जांच कैसे, क्यों व किस तरह हो रही है? क्या घोषित उद्देश्य (जो प्रायः बनावटी ही होता है) की आड़ में कोई अघोषित राजनैतिक उद्देश्य छिपा है? यही वह ''परसेप्शन'' है, जो केंद्रीय एजेंसियों की गलत कार्यशैली के कारण जनमानस में गहराते जा रहा है।

महाभारत का प्रसंग है:

'अश्वत्थामा हतः इति नरो वा कुंजरो वा' -

सच कहने का आभास, पर पूरा सच नहीं।

किसी आज जांच एजेंसियों की स्थिति भी कुछ ऐसी ही प्रतीत होती है। यह स्थिति लोकतंत्र और संघवाद-दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। कहीं यह टकराव राष्ट्रपति शासन की ''आशंका'' को तो बलवती नहीं बनाता है? अतः आज आवश्यकता है आत्ममंथन की, अन्यथा. 'फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत।' भविष्य क्या होगा, यह आज के निर्णय तय करेंगे।

पुस्तक समीक्षा

दिनेश पाठक

(वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक)

देव आनंद होने का मतलब सिर्फ अभिनय नहीं

देव आनंद के लिए उनकी दीवानगी ने उन्हें उनकी फिल्मों, फिल्मों के गीतों, उनकी हीरोइनों, उनकी चाहतों, उनकी नफरतों, उनकी कामयाबियों और नाकामियों, उनकी पसंद-नापसंद, परिवार, यार दोस्त, रिश्ते नाते जिंदगी का कोई भी पहलू विश्लेषित करने से नहीं छोड़ा। इन सारे सवालों के जवाब संजोकर ही यह किताब तैयार हुई 'मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया।'

देव आनंद की चिर युवा छवि और पीढ़ी दर पीढ़ी उनके प्रति युवाओं की करिश्माई दीवानगी के पीछे ख़ास किस्म का फलसफा हुआ करता था। आज वही फलसफा मेरे ज़ेहन में तब उभर रहा है जब मैं निर्माता, निर्देशक, अभिनेता देव आनंद की ज़िंदगी, उनकी फिल्में, उनके गीतों और उनके जीवन के सुने अनसुने किस्सो को लेकर एक ऐसे युवा लेखक के द्वारा लिखी गई किताब, के पन्ने पलट रहा हूं जिसका जन्म देव आनंद के उरूज़ के बहुत बाद में हुआ। 'मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया' किताब के लेखक दिलीप कुमार पाठक, देव आनंद की ज़बरदस्त मकबूलियत वाले दिनों के गवाह कतई नहीं रहे।

पच्चीस अध्यायों में विभाजित किताब, देव आनंद की जीवन गाथा से प्रारंभ होती है और फिर जोश और जज़्बे से भरी उनकी जिंदगी के तमाम ख़ास चैप्टर एक के बाद एक खुलते चले जाते हैं। इनमें शामिल हैं उनके प्रोडक्शन हाउस नवकेतन की स्थापना, चार्ली चैपलिन से उनकी मुलाक़ात, अभिनेत्री सुरैया से उनका अफेयर और फिर दूसरी अभिनेत्री कल्पना कार्तिक से विवाह वगैरह वगैरह। किताब की एक और खासियत है इसके वो दो अध्याय जिनमें देव आनंद की क्लासिक फिल्मों और उन फिल्मों के कल्ट गीतों की चर्चा विस्तार से की गई है। क्लासिक फिल्मों में शामिल हैं, सी.आई.डी. ,जॉनी मेरा नाम, ज्वेल थीफ, गाइड, कालापानी, तेरे मेरे सपने, हम दोनों और तेरे घर के सामने।

कल्ट गीतों वाले अध्याय में सबसे पहले जिक्र है किताब के शीर्षक मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया... गीत का। इसके बाद बारी-बारी से खोया खोया चांद, तू कहाँ ये बता, अभी न जाओ छोड़ कर, वहां कौन है तेरा मुसाफिर जाएगा कहां, पिया तोसे नैना लागे रे, तेरे मेरे सपने अब एक रंग हैं, कांटों से खींच के यह आंचल, कभी खुद पर कभी हालात पर रोना आया और रंगीला रे... के भाव, शब्द, संगीत और स्वर का विस्तार से विश्लेषण किया गया है।

देव साहब के अधूरे ख्वाब, शीर्षक वाले अध्याय में दो फिल्मों का ज़िक्र किया गया है जिनमें से एक 'द ईविल विदइन' 70 के दशक की जेम्स बॉन्ड शैली की फिल्मों की तर्ज पर बनाई गई एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म थी।इसे भारत और फिलीपींस के पारस्परिक सहयोग से नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले देव साहब ने प्रोड्यूस किया था और फ़िलिपीन के निर्देशक लैंबर्टो वी एवेलेना और इटालियन निर्देशक लुइगी जैम्पा ने डायरेक्ट किया था। दूसरी फिल्म जो सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित रही वो, मनोहर मालगांवकर की 1963 में प्रकाशित किताब 'द प्रिंसेस' पर आधारित थी। बताते हैं देव साहब ने 1960 के लगभग ही फिल्म बनाने के लिए इस उपन्यास के राइट्स खरीद लिए थे।

उनका इरादा इस कहानी को एक अंतरराष्ट्रीय स्तर की पीरियड ड्रामा फिल्म के रूप में बनाना था जो भारत के इतिहास, राजनीति और मानवीय संवेदनाओं को वैश्विक दर्शकों तक पहुंचा सके। फिल्म की अंतरराष्ट्रीय पृष्ठभूमि एवं पीरियड फिल्म होने के कारण इसके प्रोडक्शन की लागत बहुत अधिक थी। फिल्म निर्माण और कास्टिंग को लेकर भी काफी व्यावहारिक कठिनाइयां थीं। इन सब कारणों से यह फिल्म फ्लोर पर नहीं जा पाई और इस तरह देव साहब का यह सपना भी अधूरा ही रह गया।

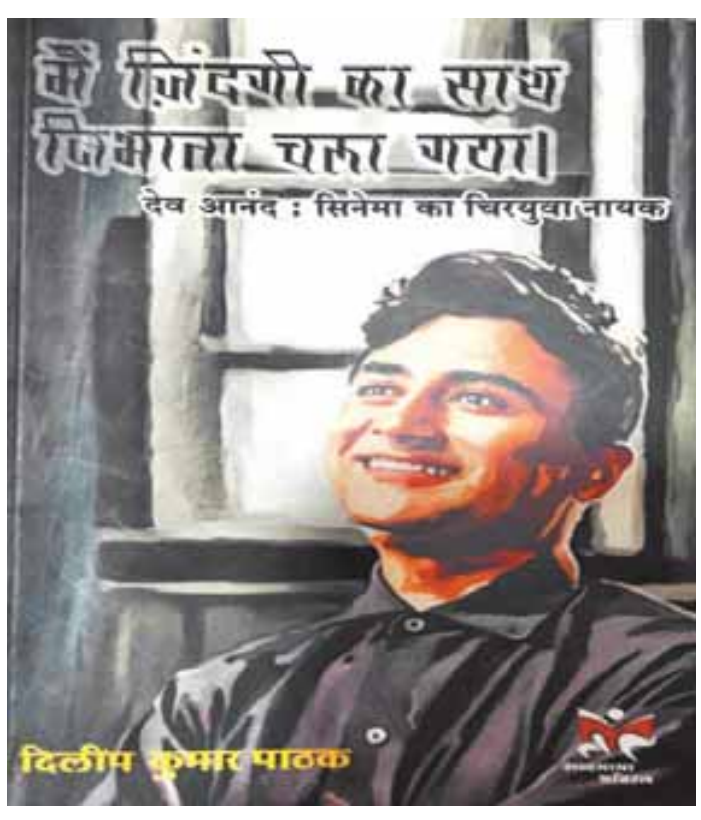

लेखक ने इस पुस्तक के जरिए देव साहब के इन दो अधूरे सपनों के बारे में बताया गया है। लेकिन, देव साहब का एक तीसरा सपना भी अधूरा रह गया था। वह था विश्वविख्यात सितार वादक भारत रत्न पंडित रविशंकर और उनकी विदेशी पुत्री ग्रैमी अवार्ड विजेता नोरा जोन्स की कहानी पर आधारित फिल्म 'द म्यूजिक ऑफ़ लाइफ्स' का निर्माण। देव आनंद ने स्वयं इन पंक्तियों के लेखक को बताया था कि इस प्रस्तावित फिल्म 'म्यूजिक ऑफ द लाइफ्स' की स्क्रिप्ट का पहला संस्करण अमेरिकन राइटर्स एसोसिएशन में जमा कर के सब्जेक्ट का कॉपीराइट मांग लिया है। इस फिल्म के अधिकांश कैरेक्टर अमेरिकन ही होंगे और यह फिल्म सिर्फ अंग्रेजी में ही बनेगी। क्योंकि, ज्यादातर पात्र अमेरिकन हैं, उनसे हिंदी बुलवाना हास्यास्पद लगेगा। भारत में भी इसका अंग्रेजी संस्करण ही रिलीज होगा। यदि, सदाबहार अभिनेता का वह सपना पूरा हो गया होता तो दर्शकों को दो दिग्गजों के रचनात्मक मिलन से प्रेरित एक बहुत ही शानदार फिल्म देखने को मिलती।

किताब में इसके अलावा देव आनंद के गीतों में रफी साहब की आवाज का महत्व, जवाहरलाल नेहरू से प्रेरित देवानंद, नेशनल पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी बनाने वाले देवानंद, देवानंद और नेपाल नरेश की मित्रता,नई प्रतिभाओं को मौका देने वाले देवानंद और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेई के साथ देव साहब की पाकिस्तान यात्रा जैसे कुछ अन्य अध्याय भी सम्मिलित किए गए हैं। इनके बारे में अधिकांश आम पाठक समाचारों में या फिर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में पूर्व में भी पढ़ चुके हैं और जानकारी रखते हैं। कुल मिला कर देव आनंद के प्रशंसकों की चार पांच पीढ़ियों के लिए इस रोचक किताब में जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है और उनके लिए भी जो जानना चाहते हैं, देव आनंद होने का मतलब !

पुस्तक : मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया
लेखक : दिलीप कुमार पाठक
पृष्ठ संख्या : 222
मूल्य : 299/ रूपए

अग्रवाल महासभा एवं वैश्य महासमेलन समाज ने बसंत पंचमी पर भोजशाला में दिनभर पूजा की अनुमति को लेकर सौंपा ज्ञापन

धार। मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा एवं वैश्य महासम्मेलन धार द्वारा बसंत पंचमी के अवसर पर भोजशाला में सूर्योदय से सूर्यास्त तक अखंड पूजा-अर्चना की अनुमति मांगी है। समाज ने गुरुवार को इस संबंध में जिला प्रशासन को एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें शांतिपूर्ण और निर्विघ्न आयोजन सुनिश्चित करने की अपील की गई। ज्ञापन कलेक्टर के नाम तहसीलदार को दिया गया। समाज ने 23 जनवरी, शुक्रवार को बसंत पंचमी एवं मां सरस्वती जन्मोत्सव के अवसर पर पूरे दिन पूजा की मांग की।

ज्ञापन में 7 अप्रैल 2003 के एक आदेश का हवाला दिया गया है। इस आदेश के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन संपूर्ण हिंदू समाज को सूर्योदय से सूर्यास्त तक पूजा-अर्चना का अधिकार प्राप्त है। समाज ने प्रशासन से इस आदेश का पालन सुनिश्चित कराने का आग्रह किया है।

समाज के पदाधिकारियों ने बताया कि भोजशाला में बसंत पंचमी पर परंपरागत रूप से पूजा-अर्चना होती रही है। यह विषय संपूर्ण हिंदू समाज की आस्था से जुड़ा हुआ है। इस अवसर पर अनंत अग्रवाल,जगदीश चंद्र अग्रवाल,कैलाश मालक, मोहन अग्रवाल, सुरेश गोयल, आशीष गोयल, गोपी किशन अग्रवाल, पराग अग्रवाल, बंसीधर अग्रवाल, अशोक मित्तल, शिव अग्रवाल, राजेंद्र अग्रवाल, रितेश अग्रवाल, सतीशचंद्र अग्रवाल, ओमप्रकाश अग्रवाल,लाड समाज से कैलाश चंद्र लाड़, जगदीश चंद्र लाड, जैन समाज से प्रवीण गुप्ता,वीरेंद्र जैन, खंडेलवाल समाज से श्याम खंडेलवाल, माहेश्वरी समाज से गोपाल राठी, विजयवर्गीय समाज से अंकुश विजयवर्गीय, नीमा समाज से राजीव गुप्ता, राजेश महाजन, शैलेष नेमा, जायसवाल समाज से मनीष जायसवाल,महिलाओं में रेखा मेहता, शोभा अग्रवाल,अनीता अग्रवाल, कुसुम अग्रवाल, पायल गोयल, वैजयंती बाला नाहर,कविता अग्रवाल, वर्षा अग्रवाल, सारिका खंडेलवाल, अर्चना खंडेलवाल, रीना गोयल, किरण मित्तल, सीमा अग्रवाल, गायत्री अग्रवाल, स्मिता अग्रवाल मौजूद थे। ज्ञापन का वाचन मध्यप्रदेश अग्रवाल महासभा के प्रदेश उपाध्यक्ष और वैश्य महासम्मेलन के जिला अध्यक्ष आशीष गोयल ने किया। जानकारी मीडिया प्रभारी श्याम मंगल लेबड़ ने दी।

ऐरण विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा जिससे रोजगार के अवसर मिलेंगे

विरासत से विकास की उड़ान शुरू होगी : राजेन्द्र शुक्ल

भोपाल। ऐरण विश्व पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा जिससे कि युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे एवं क्षेत्र समृद्ध बनेगा, विरासत से विकास की उड़ान भी शुरू होगी। उक्त विचार उपमुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने सागर जिले के बीना में तीन दिवसीय ऐरण महोत्सव के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में व्यक्त किये। इस अवसर पर विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे, नगर निगम अध्यक्ष श्री वृंदावन अहिरवार, श्री श्याम तिवारी, श्री गौरव सिरोठिया, श्री अरुणोदय चौबे, अपर कलेक्टर श्री अविनाश रावत, एसडीएम श्री विजय डेहरिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री संजीव उईके सहित अन्य जन प्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में जन समुदाय मौजूद था।

उप मुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने ऐरण महोत्सव में बोलते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में लगातार ऐतिहासिक स्थलों पर महोत्सव आयोजित कर उनकी गरिमा एवं पर्यटन को बढ़ाने का कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि निकट भविष्य में यह ऐरण विश्व पर्यटक स्थल के रूप में स्थापित होगा और यहां बड़ी संख्या में सैलानी एवं पर्यटक आएंगे उन्होंने कहा कि यहां बीना नदी के कारण यह स्थल और भी मनोरम है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक विष्णु भगवान की मूर्ति देखकर लगता है कि सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व भी यहां के कलाकार कितने कुशल एवं दक्ष होंगे, जिन्होंने इतनी अच्छी नक्काशी के माध्यम से उनको मूर्ति रूप दिया। उन्होंने कहा कि इतिहास परंपरा को आधुनिकता से जोड़ने का कार्य ऐरण महोत्सव करेगा।

प्रभारी मंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि यह ऐरण महोत्सव के माध्यम से कला संस्कृति को जहां मंच मिल रहा है वहीं संस्कृति एवं इतिहास से सभी अवगत भी हो रहे हैं।

बीना विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे ने कहा कि ऐरण महोत्सव बीना सहित बुंदेलखंड एवं मध्य प्रदेश के गौरव का पुरातत्व स्थल है जिससे पूरे विश्व में सागर की पहचान स्थापित हुई है उन्होंने कहा कि 4 सितंबर 2024 को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वादा किया था आज मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा यह वादा पूरा किया गया है उन्होंने कहा कि ऐरण बुंदेलखंड सहित विश्व की धरोहर है।

श्रीमती सप्रे ने कहा कि ऐरण को संरक्षित एवं संरक्षण करने का कार्य हम सबको करना होगा उन्होंने समस्त जन समुदाय से अपील भी की कि ऐरण क्षेत्र में जो भी मूर्ति प्राप्त होती है वह पुरातत्व विभाग को प्रदान करें ऐरण भविष्य में बड़ा पर्यटन स्थल बनेगा।

प्रभारी मंत्री ने की गंगा आरती

उपमुख्यमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने ऐरण में बीना नदी में गंगा आरती की इस अवसर पर विधायक श्रीमती निर्मला सप्रे, श्री श्याम तिवारी, श्री गौरव सिरोठिया, श्री अरुणोदय चौबे सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद थे।

प्रभारी मंत्री ने किया सम्मानित

ऐरण महोत्सव के दौरान उपमुख्यमंत्री एवं प्रभारी मंत्री श्री राजेंद्र शुक्ल ने पुरातत्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारी डॉक्टर श्री मोहन चढ़ार एवं डॉ हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विभाग अध्यक्ष डॉक्टर नागेश दुबे को शाल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मान किया। 1700 वर्ष पुराने ऐरण के विष्णु भगवान के मंदिर एवं विभिन्न अवतारों की पुरातत्व विभाग के अधिकारी डा मोहन चढ़ार एवं डॉ नागेश दुबे ने विस्तार से जानकारी दी। जिला अध्यक्ष श्री श्याम तिवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के द्वारा सभी क्षेत्र में कार्य किया जा रहे हैं और यह ऐरण महोत्सव मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव एवं उपमुख्यमंत्री एवं सागर जिले के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल के प्रयास के माध्यम से किया जा रहा है।

मकर संक्रांति पर जीव दया संस्था ने प्रकृति वात्सल्य गौशाला में गौपूजन कार्यक्रम का आयोजन किया

धार। मकर संक्रांति पर्व पर दान पुण्य का अलग ही महत्व होता है । जीवदया संस्था द्वारा प्रकृति वात्सल्य गौशाला 34 बटालियन में दान व सम्मान कार्यक्रम हुआ । धार के बंशीधर वल्लभदासजी अग्रवाल (गोकुल डेरी) ने गौशाला को 1 लाख रु दान का चेक भेंट किया जिस पर उनका सम्मान किया गया । जीवदया संस्था के प्रकाश जैन (सर), अभय जैन (वर्धमान ट्रेडर्स), अन्य दानदाताओं व गौशाला के सेवादारों का सम्मान किया गया । उल्लेखनीय है कि जीवदया विभिन्न प्रकार की समाज सेवा में हर समय तत्पर रहता है । जिसमें गायों, कुत्तों, कौओं के आहार, मछलियों का अभयदान, कोढ़ियों की बस्ती में दान व मृत्यु होने पर अंत्येष्टि की व्यवस्था करना सम्मिलित हैं। संक्रांति के दिन विशेष रूप से चींटियों को सालभर भोजन मिलता रहे इस उद्देश्य से इनके द्वारा जेसीबी से नालेनुमा गड्ढा करके, खोपरा गोले में घी आटा शक्कर मिलाकर जमीन में गाड़कर वापस मिट्टी से कवर करवा दिया जाता है । साथ ही गुड़, धान, पशु आहार आदि का दान इस संस्था के सदस्यों व अन्य गौभक्तों द्वारा किया गया।

रमेशभाई खेपर (श्रीहरि टाइल्स) ने 11000 रु व जयंतीलाल सेठिया ने भी 5000 रु गौशाला को दान किये । अनेक लोगों ने भी चारे आदि का दान गौशाला में किया । जीवदया संस्था से राजू जैन (लब्दी सेठ), प्रवीण कोठारी, प्रवीण गुप्ता, द्वारका अग्रवाल, विपिन त्रिवेदी, महावीर पावेचा, प्रकाश तांतेड़, धर्मेंद्र राठौर, चंदनबाला जैन, सपना छाजेड़, वैजयंती माला नाहर, सविता कोठारी आदि व गौशाला से विजया शर्मा, प्रमिला शर्मा, धर्मेंद्र जोशी, एड. प्रवीण शर्मा, सलिल यादव, संतोष पुरोहित, घनश्याम शर्मा, सचिन दवे, विजय अग्रवाल आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम के पश्चात शाम को धरावरा फाटे पर गौ तस्करी करते हुए जो कंटेनर पकड़ा उसके गोवंश की गौशाला ने सुपुर्दगी लेकर आश्रय दिया । श्वानों के लिए भी विभिन्न दानियों द्वारा दान किये गए।

श्रद्धालय वृद्धाश्रम में लगा सोलर ड्रायर

धार। पूरे विश्व में सौर ऊर्जा का महत्व बढ़ा है। वृद्धजनों के लिए जनसहयोग से 4 ट्रे क्षमता का सौलर ड्रायर का श्रद्धालय वृद्धाश्रम में आज शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत धार व उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी दिनेश वर्मा, भोज शोध संस्थान के निदेशक व संचालक श्रद्धालय वृद्धाश्रम डॉ दीपेंद्र शर्मा, मातृ स्मृति विद्या देवी वृद्धजन सहयोगी नीरज ग्रेवाल व उनके

परिजन उपस्थित थे। वर्मा ने कहा कि यह ड्रायर बहुत उपयोगी नवाचार है। आज आश्रम के निरीक्षण में साफ सफाई व जल स्वच्छता अच्छी मिली है। हवन कंडे व गौधूप की सराहना की। वृद्धजनों से मुलाकात की। संचालक की ओर से डॉ शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि इस सौलर ड्रायर में प्याज, अदरक, धनिया, मैथी, लौकी, टमाटर जैसे फल सब्जियां सुखाई व संरक्षित की जा सकती है। यह 21 वा नवाचार है। ड्रायर में सूखने के समय कम लगेगा। स्वच्छता, संक्रमण रहितता, प्रोटीन व विटामिन बने रहते है। यह उपयोगी संसाधन उपलब्ध होने से मौसमी सब्जियों व फलों का पावडर तैयार करने में भी मदद मिलेगी व वृद्धजन भी इसका उपयोग कर सकेंगे। जानकारी मीडिया प्रभारी राकी मक्कड़ ने दी।

लांगाबम्हौरी, चीचली पुलिया, रानी पिपरिया चिन्हित स्थानों पर आए दिन होते हैं हादसे, 3 व्यक्तियों की मृत्यु

हीरालाल गोलानी सोहागपुर

सोहागपुर विधानसभा के लांगाबम्हौरी चीचली पुलिया एवं रानी पिपरिया चिन्हित स्थानों पर आए दिन होते हैं, सड़क हादसे। गत रात्रि अलग-अलग सड़क दुर्घटना में 03 व्यक्तियों की मृत्यु एवं 01 व्यक्ति घायल हुए हैं। पहली घटना में अनिल पटेल निवासी बमौरी की रिपोर्ट पर बमौरी के राजू पटेल ने सूचना दी कि भांजा अरविंद पटेल एवं भतीजा राजकुमार पटेल का गुलौन मोड़ के पास एक्सीडेंट हो गया है। तब अनिल पटेल ने जाकर देखा कि अरविंद पटेल एवं राजकुमार पटेल एक्सीडेंट में घायल होकर नीचे पड़े हुए थे। एक्सीडेंट करने वाली कार स्विफ्ट एमपी 04 जेडजी 8559 के चालक के द्वारा अरविंद पटेल एवं रमेश पटेल को टक्कर मारकर मौके से गाड़ी छोड़कर भाग गया है।दोनों को अस्पताल सोहागपुर लेकर आए जहां डॉक्टरों ने अरविंद एवं राजकुमार को मृत घोषित कर दिया। वहीं दूसरी घटना में सुबह करीबन 4:00 बजे कपिल पिता राकेश दीवान कुचबंदिया उम्र 37 वर्ष निवासी अंबेडकर वार्ड पिपरिया जो अपने दोस्त के साथ बाबई से मोटरसाइकिल से गमी के कार्यक्रम पश्चात देर रात्रि पिपरिया के लिए निकले थे। बाबई से पिपरिया आते समय सेंट पैट्रिक स्कूल एवं चीचली पुलिया के बीच एक्सीडेंट हो गया। जिसमें कपिल की मृत्यु हो गई। एक्सीडेंट का कारण अभी अज्ञात है। दोनों प्रकरण में मर्ग कायम कर जांच में लिया गया है वहीं तीसरी घटना में संदीप धुर्वे पिता गोपाल धुर्वे निवासी छेड़का सोहागपुर उम्र 22 वर्ष जो रात्रि में सड़क दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल आए । अधिक चोट होने से जिला अस्पताल नर्मदापुरम रवाना किया गया। नगर निरीक्षक उषा मरावी, एएसआई गणेश राय एवं सोहागपुर पुलिस ने सभी आमजन से अपील है कि तेज रफ्तार से वाहन न चलाएं, नशा करके वाहन न चलाएं, हेलमेट एवं सीट बेल्ट का प्रयोग करें ।रात्रि के समय दो पहिया वाहन से लंबे सफर पर न चलें।, चारपहिया वाहनों में लंबी दूरी का सफर करने के लिए कुशल चालकों के साथ चले तभी दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है।

नगरपालिका ने बनाया कंट्रोल रूम, पेयजल संबंधित कर सकते हैं शिकायतें

अब लोगों के सामने मौके पर ही होगी पानी की जांच

एस. द्विवेदी, बैतूल। हाल ही के दिनों में इंदौर में प्रदूषित पानी की घटना के बाद बैतूल नगरपालिका ने शहर की जल प्रदाय व्यवस्था को लेकर सतर्कता बरतना शुरू कर दिया गया है। नपा बैतूल की जल शाखा विभाग द्वारा शहर में सप्लाई पेयजल के सैंपल लेकर जांच करवाई जा रही है। हालांकि जो पानी शहर में सप्लाई होता है, इसकी सप्लाई के पहले भी जांच की जाती है। इसके बाद यह पानी शहर की टंकियों में भेजा जाता है, लेकिन इंदौर की घटना के बाद लोगों में पेयजल को लेकर जो डर बना हुआ है, उसे दूर करने हेतु नगरपालिका ने हर वार्ड के पांच-पांच घरों से पानी का सैंपल कलेक्ट करने का काम भी शुरू कर दिया है, जिसकी नपा की लैब में टेस्टिंग की जाती है। यहां उल्लेखनीय है कि नदी से जो रॉ-वॉटर फिल्टर प्लांट पर आता है, तो वहां जल का शुद्धिकरण किया जाता है। इसके बाद टैंक भरकर इस पानी की सप्लाई शहर की विभिन्न टँकियों में की जाती है, जिसके माध्यम से शहर में पानी की सप्लाई की जाती है। लेकिन इंदौर की घटना के बाद लोगों में पेयजल को लेकर जो तरह-तरह की भ्रांतियां पैदा हो रही थी, उस संदेह को दूर करने के लिए नगरपालिका ने हर वार्ड के पांच-पांच घरों से पानी सैंपल लेकर

जांच करने का अभियान शुरू कर दिया है, ताकि लोग के संदेह व शंकाओं को दूर किया जा सके।

घरों में मौके पर ही होगी पानी की जांच – नगरपालिका ने पानी की जांच के लिए किट मंगवाई है, जिससे घरों में मौके पर ही पानी की जांच हो सकेगी। नपा बैतूल की जल शाखा के सब इंजीनियर धर्मेन्द्र राठौर ने बताया कि नगरपालिका की लैब में पानी की जांच की जाती थी, लेकिन अब घरों में सप्लाई किए जाने वाले पानी की जांच लोगों के सामने ही की जायेगी। इसके लिए जो किट की आवश्यकता पड़ती है, वह नगरपालिका ने मंगवा ली है। जिसके माध्यम से घरों तक पहुंचने वाले पानी की जांच लोगों के सामने ही हो सकेगी। इसका यह फायदा होगा कि लोगों के बीच में पानी को लेकर जो शंकाएं है, उनका लोगों के सामने ही समाधान किया जा सकेगा।

जन सुनवाई के लिए कंट्रोल रूम स्थापित – नगरपालिका ने पानी से संबंधित समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु नपा कार्यालय में एक कंट्रोल रूम शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि पानी की सप्लाई व्यवस्था के तहत शहर को 4 जोन में बांटा गया है। इन सभी जोनों से रोजाना 4-5 सैंपल लिए जा रहे हैं और इनकी जांच कराई जा रही है। इसके अलावा नपा कार्यालय में ही एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। इस कंट्रोल रूम के प्रभारी पंकज सोनी और कमलाकर टोंग को बनाया गया है। नगरवासी, कंट्रोल रूम या प्रभारियों के नंबरों पर गंदे पानी या लीकेज आदि की शिकायत कर सकते हैं। जिनका त्वरित निराकरण किया जाएगा।

नगरीय प्रशासन विभाग के उपसंचालक ने किया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एवं टंकियों का निरीक्षण

बैतूल। नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल के उप संचालक ओपी ओझा ने बैतूल सहित जिले की विभिन्न नगरपालिकाओं और नगर परिषद का निरीक्षण कर पेयजल सप्लाई संबंधित व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान पानी सप्लाई करने वाले वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल टंकियों का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि बैतूल जिले के निरीक्षण के लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल के उप संचालक ओपी ओझा इन दिनों बैतूल पहुंचे हैं, उन्होंने जलावर्धन योजना के तहत वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, पेयजल टंकियों एवं अन्य संरचनाओं का निरीक्षण किया। उपसंचालक के साथ नगरपालिका के जल शाखा प्रभारी सब इंजीनियर धर्मेन्द्र राठौर, नगेंद्र वागद्रे, जल शाखा प्रभारी भवेन्द्र मालवीय, सुपर वाईजर अशोक डेंगे, सुखदेव बारस्कर, प्रमोद चौरसिया आदि उपस्थित थे। उपसंचालक ने निरीक्षण के दौरान नपा की बेहतर कार्यशैली की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि निकाय क्षेत्र में बेहतर पेयजल संरचना है और इसका संचालन भी बेहतर तरीके से किया जा रहा हैं। अधिकारियों को सभी संरचनाओं की सतत निगरानी रखने के लिए कई सुझाव भी उन्होंने दिए।

इनका कहना है –

नपा को पानी की जांच के लिए किट मिल चुकी है। अब लोगों के घरों तक पहुंचने वाले पानी की जांच उनके सामने ही हो पायेगी। अभी तक सेम्पल लेकर पानी की जांच लैब में कराना पड़ रहा था। नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल के उप संचालक ओपी ओझा ने भी नपा के पेयजल सप्लाई का निरीक्षण किया है। उनके सामने भी नल के पानी की जांच की गई। जिसमें पानी शुद्ध पाया गया।

– **धर्मेन्द्र राठौर,** सब इंजीनियर, जल शाखा, नपा बैतूल

ताप्ती जीवनदायिनी, संस्कृतियों की पोषक और पवित्रता का प्रतीक

बैतूल /मुलताई। मप्र शासन के संस्कृति विभाग द्वारा जिला प्रशासन बैतूल, नपा परिषद मुलताई एवं दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, नागपुर के सहयोग से आयोजित तीन दिवसीय ताप्ती महोत्सव का शुभारंभ हाई स्कूल मैदान, मुलताई में हुआ। यह आयोजन मकर संक्रांति के पावन पर्व पर नदियों की महिमा और संरक्षण का संदेश देते हुए प्रारंभ हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में दर्शक-श्रोता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ अवसर पर सांसद एवं केंद्रीय राज्य मंत्री (जनजातीय कार्य विभाग, भारत सरकार) दुर्गादास उइके मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुलताई विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने की। विशेष अतिथि के रूप में जन अभियान परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर, जिला विकास सलाहकार समिति सदस्य सुधाकर पंवार तथा नगर पालिका परिषद अध्यक्ष वर्षा गड़ेकर उपस्थित रहीं। ताप्ती महोत्सव के द्वितीय दिन का आरंभ सुगम संगीत से हुआ, जिसमें संजय श्रीवास्तव ने अपनी सुमधुर प्रस्तुति देकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। इसके पश्चात आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में जानी बैरागी, भुवन मोहिनी, अमन अक्षर, दीपक शुक्ला सहित अन्य कवियों ने अपनी रचनाओं से श्रोताओं को भावविभोर कर दिया और सभागार में काव्यरस की वर्षा कर दी।

अमृतधारा—ताप्ती समवेत प्रस्तुति ने दिया संरक्षण का संदेश- मध्यप्रदेश शासन के संस्कृति विभाग द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई अमृतधारा–ताप्ती समवेत प्रस्तुति का प्रथम मंचन महोत्सव के शुभारंभ अवसर पर किया गया। इस प्रस्तुति के माध्यम से ताप्ती नदी के जरिए नदी, पर्वत, जंगल, प्रकृति एवं जल संरक्षण का सशक्त संदेश दिया गया। प्रस्तुति का आरंभ मां ताप्ती के उद्गम की पौराणिक कथा से हुआ। लगभग 740 किलोमीटर की यात्रा तय करने वाली यह पावन नदी केवल जल स्रोत ही नहीं, बल्कि जीवनदायिनी, संस्कृतियों को जन्म देने वाली और पवित्रता की प्रतीक है। प्रसिद्ध अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी ने सूत्रधार के रूप में कथा को जीवंत किया। उनके साथ बाल कलाकार वान्या दत्ता ने नई पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हुए प्रकृति संरक्षण का संकल्प प्रस्तुत किया। हिमानी शिवपुरी परंपराओं का प्रतीक बनीं, वहीं वान्या ने परंपराओं को आगे बढ़ाने का संदेश दिया। भरतनाट्यम, कथक, कटेंपरेरी, कोरकू, सैला, गदली, गणगौर एवं बुंदेली नृत्य शैलियों के सुंदर समन्वय ने प्रस्तुति को अत्यंत प्रभावशाली बना दिया। इस प्रस्तुति में मध्यप्रदेश के लगभग 80 कलाकारों ने सहभागिता की। प्रस्तुति की परिकल्पना एवं लेखन वीनस तरकसवार, निर्देशन व संगीत संयोजन उमेश तरकसवार, नृत्य निर्देशन श्वेता देवेंद्र, संगीत संचालन कबीर तरकसवार, प्रकाश परिकल्पना आदर्श शर्मा तथा वेशभूषा अर्चना शैलेन्द्र द्वारा किया गया।

इष्टदेव 'बिरूआ' की महिमा में धनगरी गाजा नृत्य- इसके पश्चात महाराष्ट्र के सांगली जिले से आए कलाकारों द्वारा पारंपरिक धनगरी गाजा नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। अनिल भीमराव कोलेकर एवं साथी, सांगली द्वारा प्रस्तुत इस नृत्य में ढोल, कैताळ, बांसुरी और घुंघरुओं की ताल पर कलाकारों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। यह नृत्य भगवान शंकर द्वारा माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए किए गए तांडव से प्रेरित माना जाता है। यह कला सांगली जिले के आरेवाड़ी गांव के एक ही परिवार द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित की जा रही है, जिसे वर्तमान में उनकी पांचवीं पीढ़ी प्रस्तुत कर रही है। महोत्सव के प्रथम दिन की अंतिम प्रस्तुति सुप्रसिद्ध भजन गायिका सुरभि चतुर्वेदी एवं साथी (जयपुर) द्वारा दी गई। सुरभि की मधुर और भावपूर्ण आवाज़ ने श्रोताओं को भक्ति रस में सराबोर कर दिया। मां ताप्ती के उद्गम स्थल पर प्रस्तुति देते हुए उन्होंने स्वयं को धन्य महसूस किया।

स्व. सतीश मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि पर भावभीनी श्रद्धांजलि

बैतूल। भौंरा क्षेत्र के प्रतिष्ठित समाजसेवी एवं भाजपा शाहपुर के पूर्व मंडल अध्यक्ष पंडित स्व. सतीश मिश्रा की प्रथम पुण्यतिथि गुरुवार को पहावाड़ी में श्रद्धा, सम्मान और आत्मीय स्मरण के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उनके परिजनों द्वारा श्रीरामचरितमानस के सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय राज्यमंत्री डीडी उईके, भाजपा जिलाध्यक्ष सुधाकर पवार, विधायक गंगा सज्जनसिंह उइके, जिला महामंत्री कमलेश सिंह, जिला महामंत्री कृष्णा गायकी, जिला उपाध्यक्ष राजेंद्र मालवीय, शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष रोहित विक्की नायक, पूर्व विधायक मंगल सिंह धुर्वे, मंडल अध्यक्ष नीतू गुप्ता सहित बडी संख्या में कार्यकर्ता, शुभचिंतक उपस्थित रहे। दोपहर 12 बजे आरंभ हुए कार्यक्रम में

सभी ने स्व. मिश्रा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।

केंद्रीय राज्यमंत्री डीडी उइके ने कहा कि पं. मिश्रा अपने सरल स्वभाव, स्नेहिल व्यवहार और आदर्श जीवनशैली के लिए सदैव स्मरण किए जाते रहेंगे। समाज और संगठन के प्रति उनका समर्पण अनुकरणीय रहा है। परिजनों ने बताया कि पं. स्व. मिश्रा ने अपने जीवन में जो संस्कार, मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना दी, वह आज भी लोगों के हृदय में जीवित है। वे परिवार के साथ-साथ समाज के लिए भी एक मार्गदर्शक व्यक्तित्व थे। कार्यक्रम के माध्यम से उनके विचारों और योगदान को स्मरण करते हुए सभी ने उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया।

संक्षिप्त समाचार

उमंग, उत्साह और हर्षोल्लास से मनाया जाएगा गणतंत्र दिवस समारोह

सीहोर (निप्र)। जिले में गणतंत्र दिवस समारोह धूमधाम और पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इसके लिए सभी आवश्यक तैयारियां व इंतजाम सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला पंचायत सभाकक्ष में कलेक्टर श्री बालागुरू के. की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने संबंधित अधिकारियों को सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की व्यवस्थाएं समय पूर्व सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर प्रस्तुत की जाने वाली अनेक विभागों की झांकी के लिए झांकी बनाने के पूर्व थीम अनुमोदित कराने के निर्देश दिए। बैठक में जानकारी दी गई कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर झांकियों में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला बाल विकास, उद्यानिकी, पशुपालन, कृषि, जल संसाधन, सामाजिक न्याय, पंचायत ग्रामीण विकास सहित अनेक विभागों द्वारा उपलब्धियों को दर्शाती एवं जागरूकता का संदेश प्रसारित करने वाली चलित झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी।

पाहनबर्री व रामपुर में चला कृषि रथ, किसानों को मिली योजनाओं की जानकारी

नर्मदापुरम (निप्र) मध्यप्रदेश शासन द्वारा वर्ष 2026 को कृषि वर्ष के रूप में मनाए जाने के निर्देशों के तहत विकासखंड नर्मदापुरम की ग्राम पंचायत पाहनबर्री एवं रामपुर में कृषि रथ चलाया गया। कार्यक्रम के माध्यम से कृषकों को कृषि से संबंधित विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी दी गई। कृषि महाविद्यालय पवारखेड़ा की कृषि वैज्ञानिक डॉ रीता नरवरिया ने कृषि को लाभकारी व्यवसाय बनाने के उपाय बताए साथ ही उन्होंने फसल विविधीकरण एवं खाद्य प्रसंस्करण की जानकारी दी बीटीएम आत्मा श्री गौरव तिवारी ने प्राकृतिक खेती के महत्व पर प्रकाश डाला। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी श्रीमती जयश्री देशमुख ने ई-टोकन एवं उर्वरक वितरण प्रणाली की जानकारी दी। उद्यानिकी विभाग से सुश्री विजयलक्ष्मी बलबंदे ने उद्यानिकी योजनाओं की जानकारी दी, वहीं पशुपालन विभाग से श्री कैलाशचंद सावनेर ने पशुपालन योजनाओं से कृषकों को अवगत कराया। कार्यक्रम में सहायक संचालक कृषि श्रीमती अर्चना परते, कृषि विस्तार अधिकारी महक चतुर्वेदी, पटवारी, सचिव, सरपंच सहित बड़ी संख्या में कृषक उपस्थित रहे।

धरती आबा अभियान अंतर्गत ग्राम दाऊद बासौदा में जाति प्रमाण पत्रों का वितरण

विदिशा (निप्र)। धरती आबा अभियान के अंतर्गत विकासखंड बासौदा के ग्राम दाऊद में विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के दौरान पात्र हितग्राहियों को जाति प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारियों एवं संबंधित विभाग के कर्मचारियों की उपस्थिति में ग्रामीणों के लंबित आवेदनों का निराकरण किया गया। कैंप का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण एवं जनजातीय वर्ग के लोगों को शासन की योजनाओं का त्वरित एवं पारदर्शी लाभ प्रदान करना रहा। कैंप में बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे और जाति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उन्होंने शासन एवं प्रशासन के प्रति संतोष व्यक्त किया। अधिकारियों ने बताया कि ऐसे शिविरों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवश्यक दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के अनावश्यक चक्कर न लगाने पड़ें। धरती आबा अभियान के तहत आगे भी ऐसे शिविर आयोजित कर अधिक से अधिक पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।

पीएम श्री विद्यालय में स्थापित हुआ 'विजन 'फॉर राइजिंग इंडिया' सेल्फी प्वाइंट'

विदिशा (निप्र)। पीएम श्री महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पीएम श्री योजना के अंतर्गत एक आकर्षक सेल्फी प्वाइंट स्थापित किया गया है। यह सेल्फी प्वाइंट 'विजन फॉर राइजिंग इंडिया' की थीम पर आधारित है, जिसमें वर्ष 2047 तक के लिए पीएम श्री योजना के शैक्षणिक उद्देश्यों और राष्ट्र निर्माण की परिकल्पना को प्रभावशाली ढंग से दर्शाया गया है। सेल्फी प्वाइंट में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल सिद्धांतोंकृगुणवत्तापूर्ण शिक्षा, कौशल विकास, नवाचार, समावेशिता एवं वैश्विक दृष्टिकोणकृको केंद्र में रखा गया है। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को भविष्य के भारत की संकल्पना से जोड़ना तथा उनमें आत्मगौरव और प्रेरणा का संचार करना है। विद्यालय परिसर में लगाए गए इस सेल्फी प्वाइंट को लेकर छात्राओं में विशेष उत्साह देखने को मिला। छात्राएं इसे देखकर न केवल आकर्षित हुईं, बल्कि पीएम श्री योजना के लक्ष्यों और 2047 के विकसित भारत के विजन को भी समझने के लिए प्रेरित हुईं।विद्यालय की प्राचार्य डॉ. दीप्ति शुक्ला ने बताया कि यह सेल्फी प्वाइंट पीएम श्री स्कूलों के 2047 विजन को दर्शाता है, जो पूरी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सिद्धांतों पर केंद्रित है। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की नवाचारी पहलें विद्यार्थियों में सकारात्मक सोच, नेतृत्व क्षमता और राष्ट्र निर्माण की भावना को मजबूत करती हैं।

शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना लागू- 322 करोड़ 34 लाख रुपये की स्वीकृति

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद की बैठक मंगलवार को मंत्रालय में हुई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव सहित मंत्रि-परिषद के सदस्य बैठक में टैबलेट के साथ शामिल हुए। मंत्रि-परिषद द्वारा शैक्षणिक संवर्ग के सहायक शिक्षक, शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक संवर्ग के प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षकों के लिए 1 जुलाई 2023 अथवा उसके बाद की तिथि से 35 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर, चतुर्थ क्रमोन्नत वेतनमान योजना प्रभावशील किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए 322 करोड़ 34 लाख रूपये की स्वीकृति दी गई है।

द्वितीय चरण में सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा द्वितीय चरण के लिए 200 सर्वसुविधा युक्त सांदीपनि विद्यालय की स्थापना के लिए अनुमानित व्यय 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई। द्वितीय चरण के प्रस्तावित विद्यालयों की क्षमता एक हजार से अधिक होगी।

उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा सिंहस्थ-2028 के दृष्टिगत उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना लागत 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई।

सहायक उप निरीक्षक स्व. गौतम के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि स्वीकृत : मंत्रि-परिषद द्वारा जिला मऊगंज में हुई घटना में दिवंगत स्व. रामचरण गौतम, सहायक उप निरीक्षक के परिवार को 90 लाख रुपये की श्रद्धा निधि दिये जाने की स्वीकृति दी गयी। उल्लेखनीय है कि दिवंगत स्व. गौतम के परिवार को 10 लाख रुपये की विशेष अनुग्रह राशि पूर्व में 1 अप्रैल 2025 को प्रदान की जा चुकी है। जिला मऊगंज थाना शाहपुर अंतर्गत ग्राम गडरा में एक परिवार के लोगों को समुदाय के लोगों द्वारा बंधक बना लिया गया था। घर के अंदर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद शव को अभिरक्षा में लेने के दौरान समुदाय द्वारा पुलिस अमले पर हमला कर दिया था। हमले में श्री गौतम ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए कर्तव्य का पालन किया और वीर गति को प्राप्त हुए। ग्वालियर व्यापार एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला-2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50त्न छूट दिये जाने की स्वीकृति मंत्रि-परिषद द्वारा ग्वालियर व्यापार मेला-2026 एवं उज्जैन विक्रमोत्सव व्यापार मेला 2026 में ऑटोमोबाइल विक्रय पर मोटरयान कर में 50 प्रतिशत छूट दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई।

सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश की ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तीन सोलर सह स्टोरेज प्रदाय परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृति अनुसार रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर लिमिटेड द्वारा विकसित की जा रही परियोजना के अंतर्गत सोलर-सह चार घंटे 300 मेगावाट, सोलर सह छह घंटे 300 मेगावाट एवं सोलर-सह 24 घंटे 200 मेगावाट विद्युत प्रदाय की सिंगल साइकिल चार्जिंग आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस परियोजना से राज्य में पीक डिमांड के समय भी सस्ती, स्वच्छ एवं भरोसेमंद विद्युत उपलब्ध हो सकेगी।

सौर ऊर्जा परियोजनाओं से उपलब्ध विद्युत केवल दिन के समय उपलब्ध रहती है और इसकी उपलब्धता मौसम पर निर्भर करती है। इसी प्रकार पवन ऊर्जा परियोजनाओं से ऊर्जा की उपलब्धता भी अनिश्चित रहती है, क्योंकि यह पवन की उपलब्धता एवं गति पर निर्भर करती है। मध्यप्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा की बढ़ती हिस्सेदारी, ग्रिड स्थिरता की आवश्यकता, पीक-डिमांड प्रबंधन तथा विद्युत की चौबीसों घंटे उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा आधारित ऊर्जा भंडारण परियोजनाओं की स्थापना अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राजगढ़ एवं रायसेन जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा राजगढ़ एवं रायसेन जिले की सिंचाई परियोजनाओं के लिए 898 करोड़ रूपये से अधिक की स्वीकृति प्रदान की गयी है। स्वीकृति अनुसार राजगढ़ जिले की सारंगपुर तहसील की मोहनपुरा विस्तारीकरण (सारंगपुर) सिंचाई परियोजना लागत 396 करोड़ 21 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे सारंगपुर तहसील के 26 ग्रामों की 11,040 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, जिसमें 10 हजार 400 कृषक परिवार लाभांवित होंगे। मंत्रि-परिषद द्वारा रायसेन जिले की सुल्तानपुरा उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 115 करोड़ 99 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई।

इससे सुल्तानपुर तहसील के 20 ग्रामों की 5,700 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई उपलब्ध होगी, इसमें 3,100 कृषक परिवारों को लाभ होगा। रायसेन जिले की बरेली तहसील की बारना उद्वहन सिंचाई परियोजना लागत 386 करोड़ 22 लाख रुपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई। इससे बरेली तहसील के 36 ग्रामों की 15 हजार हैक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होगी, जिसमें 6,800 कृषक परिवार लाभांवित होंगे।

मध्यप्रदेश स्पेसटेक नीति-2026 लागू किये जाने की स्वीकृति : मंत्रि-परिषद द्वारा प्रदेश में उपलब्ध 322 औद्योगिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर और 31 गीगावाट की बिजली आपूर्ति, उत्कृष्ट शैक्षणिक सस्थानों आदि संसाधनों एवं अनुकुल वातावरण के दृष्टिगत अंतरिक्ष-ग्रेड विनिर्माण की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में म.प्र. स्पेसटेक नीति-2026÷ लागू की जाने की स्वीकृति दी। यह नीति उपग्रह निर्माण, भू स्थानिक विश्लेषण और डाउन स्ट्रीम अनुप्रयोगों में नवाचार को बढ़ावा देगी।

द्वितीय चरण में 200 सांदीपनि विद्यालयों के लिए 3 हजार 660 करोड़ रुपये की स्वीकृति, उज्जैन शहर की जल आवर्धन योजना के लिए 1,133 करोड़ 67 लाख रुपये स्वीकृत

मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण को 3 वर्षों के लिए 5 हजार करोड़ स्वीकृत

प्रदेश के समस्त नगरीय निकायों में अधोसंरचना विकास के लिए मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना पंचम चरण को 3 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2026-27 एवं 2028-29) के लिए, 5 हजार करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गयी है। योजनान्तर्गत मास्टर प्लान की सड़कें जिले की प्रमुख एवं अन्य रोड तथा शहर की प्रमुख सड़कों का निर्माण तथा अनुषांगिक कार्य, सडक सुरक्षा एवं शहरी यातायात सुधार, शत-प्रतिशत पेयजल आपूर्ति/सीवरेज / अन्य परियोजनाओं में गैप कवरेज से संबंधित कार्य, इंटरसेप्शन एवं डायवर्जन ड्रेन तथा एसटीपी निर्माण संबंधी कार्य एवं राज्य शासन की प्राथमिकता के कार्य किये जा सकेंगे। योजना का क्रियान्वयन नगरीय निकायों द्वारा किया जायेगा। इस योजना के लागू होने से विभिन्न शहरों में आवश्यक अधोसंरचनाएँ उपलब्ध हो सकेंगीं।

अन्य निर्णय : मंत्रि-परिषद द्वारा वर्ष 2026-27 की आबकारी नीति के निर्धारण के लिए मंत्रि-परिषद समिति गठन की स्वीकृति प्रदान की गई।

प्रदेश में खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई जा रही हैं हर संभव सुविधाएं: श्री उइके

हरदा (निप्र)। पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन सुशासन दिवस से हरदा में प्रारम्भ कमल युवा खेल महोत्सव का समापन स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस के अवसर पर सोमवार को हुआ। इस अवसर पर केन्द्रीय राज्यमंत्री श्री दुर्गादास उइके, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री गजेन्द्र शाह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती भारतीय राजू कमेड़िया, पूर्व कृषि मंत्री श्री कमल पटेल, जिला अध्यक्ष श्री राजेश वर्मा, नगर पालिका अध्यक्ष टिमरनी श्री देवेन्द्र भारद्वाज, पूर्व विधायक टिमरनी श्री संजय शाह, जिला पंचायत उपाध्यक्ष श्री दर्शन सिंह गहलोत, नगर पालिका उपाध्यक्ष श्री अंशुल गोयल जिला ओलम्पिक संघ के अध्यक्ष श्री संदीप पटेल सहित अन्य जनप्रतिनिधि व खिलाड़ी उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। समापन अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री उइके ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कार वितरित किये।

इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री उइके ने सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश व केन्द्र सरकार खिलाड़ियों व खेलों के प्रोत्साहन के लिये सराहनीय कार्य कर रही है। उन्होने कहा कि स्वास्थ्य के लिए खेल बहुत जरूरी हैं। हरदा में यह आयोजन अत्यंत सराहनीय है क्योंकि जिला स्तर पर आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में ओलंपिक नियमों और मापदंडों के अनुसार बच्चों को खेल खिलाए गये है। उन्होने कहा कि प्रदेश में खिलाड़ियों को सरकार हर संभव सुविधा उपलब्ध करा रही है। खेल को केवल खेलने के लिये नहीं बल्कि जीतने की भावना से खेलना चाहिए तभी सफलता मिलेगी। उन्होने कहा कि पिछले वर्षों में देश के बहुत से खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का नाम रौशन किया है।

उल्लेखनीय है कि आयोजन में 29 खेलों में लगभग 5 हजार खिलाड़ी शामिल हुए हैं। कमल युवा खेल महोत्सव में हैण्डबॉल, फुटबॉल, व्हालीबॉल, रस्साकसी, टेबल टेनिस, खो खो, बैडमिन्टन, कबड्डी, एथेलेटिकक्स, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर दौड़, लम्बी कूद गोला व भाला, और चकरी फेंक सहित कुल 29 खेलों के मैच आयोजित किए गये।

मिशन शक्ति हब फॉर एम्पोवरमेंट ऑफ वूमेन

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर श्री अंशुल गुप्ता के निर्देशन एवं महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी श्रीमती विनीता कांसबा के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास परियोजना विदिशा नवीन अंतर्गत सेक्टर युवराज क्लब की समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा मंगल दिवस में गोद भराई कार्यक्रम का आयोजन गायत्री मंदिर में किया गया जिसमें 50 महिलाओं के गोद भराई का कार्यक्रम संपादित किया गया। निर्धारित समय पर अस्पताल में प्रसव कराना चाहिये ताकि जच्चा-बच्चा दोनों सुरक्षित रहें। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती गीता कैलाश रघुवंशी एवं श्रीमती सरोज टंडन के द्वारा गोद भराई कार्यक्रम किया गया। उक्त कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती प्रीति शर्मा एवं महिला एवं बाल विकास के परियोजना अधिकरी, समस्त पर्यवेक्षक एवं समस्त कार्यकर्ता कार्यक्रम उपस्थित रहे। कार्यक्रम में गायत्री परिवार की दीदियों के द्वारा गर्भ से जुडे संस्कार एवं पोषण के बारे में विस्तृत रुप से जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि जैसे जमीन होगी वैसा ही फसल होगी। उसी तरह गर्भवती माता गर्भावस्था के दौरान अपना ध्यान रखेगी साथ ही खुश रहे अच्छे साहित्य का अध्ययन करें इन सब का प्रभाव उनके गर्भस्थ शिशु पर पडता है। माता को गर्भावस्था के दौरान अपने वजन की नियमित जॉच करानी चाहिये समय पर निर्धारित टीके लगवाने चाहिये एनीमिया की जॉच करवानी चाहिये।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन की कार्रवाई

नर्मदापुरम (निप्र)। खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा कालिका नगर नर्मदापुरम स्थित नर्मदा बैकरी एवं पेटिस पार्लर की जांच की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार एवं जितेंद्र सिंह राणा द्वारा निरीक्षण के दौरान गंदगी में ब्रेड एवं टोस्ट का निर्माण होना पाया। बैकरी संचालक द्वारा परिसर की साफ सफाई नहीं की जा रही है और मकड़ी के जाले और अस्वच्छ वातावरण में ब्रेड पेटिस और टोस्ट का निर्माण किया जाना पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत कार्यवाही की गई।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी कमलेश दियावार द्वारा ब्रेड और टोस्ट के नमूने जांच हेतु लिए गए। विक्रेता को नोटिस जारी किया जा रहा है। संगृहीत नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जा रहा है रिपोर्ट प्राप्त होने पर अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त विक्रेता के द्वारा खाद्य पदार्थों पर निर्माण तिथि और अवसान तिथि का उल्लेख नहीं किया जा रहा है। सुधार होने तक निर्माण इकाई का संचालन न करने का निर्देश दिए गए है और इसलिए तुरंत प्रभाव से निर्माता का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में प्रारंभ हुआ 'संकल्प से समाधान अभियान'

नर्मदापुरम (निप्र)। मध्य प्रदेश शासन के विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को साकार करने के उद्देश्य से शासन के समस्त विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने हेतु संकल्प से समाधान अभियान का आयोजन किया जा रहा है। यह अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक ग्राम पंचायत, नगरीय निकाय, तहसील एवं जिला स्तर पर संचालित किया जाएगा।

अभियान के अंतर्गत भारत सरकार एवं राज्य शासन की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के साथ-साथ अन्य सेवाओं का लाभ योजनाओं के लिए निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप पात्र हितग्राहियों को प्रदान किया जाएगा। जिले में

संकल्प से समाधान अभियान का सफल आयोजन कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले के सभी अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम), जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ) एवं नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारी (सीएमओ) द्वारा अभियान के प्रथम चरण के लिए ग्राम/वार्ड स्तरीय समितियों एवं नोडल अधिकारियों की टीमों का गठन कर तैनाती की गई है। साथ ही, सीईओ जिला पंचायत से समन्वय कर अभियान से संबंधित आवश्यक डेटा एंट्री को पोर्टल पर सुनिश्चित करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। अभियान के तारतम्य में जिले के विभिन्न स्थानों पर संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

जनप्रतिनिधियों ने किया नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण

सीहोर (निप्र)। विधायक श्री सुदेश राय, भाजपा जिला अध्यक्ष श्री नरेश मेवाड़ा और नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रिंस राठौर ने सीहोर के वार्ड क्रमांक 34 में नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक का लोकार्पण किया। सीएमएचओ डॉ सुधीर डेहरिया ने बताया कि इस नवनिर्मित मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक से 07 वार्डों के नागरिकों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं आसानी से उपलब्ध होंगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री संजीवनी क्लीनिक प्रदेश सरकार द्वारा शहरी क्षेत्रों में लोगों को घर के पास मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। जहाँ सामान्य बीमारियों का इलाज, दवाइयां, पैथोलॉजी जाँचें और विशेषज्ञ डॉक्टर की सलाह जैसी सुविधाएँ आसानी से मिलती हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाएँ सुलभ हो रही हैं। कार्यक्रम के दौरान डीएचओ डॉ मालती आर्या, डॉ पिकेश अग्रवाल, श्री राजकुमार गुप्ता, सहायक कार्यक्रम प्रबंधक श्री हरिओम मेवाड़ा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी उपस्थित थे।

कलेक्टर ने जिले में 'संकल्प से समाधान' अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के दिए निर्देश

सीहोर (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के निर्देशानुसार युवा दिवस 12 जनवरी से प्रदेश में प्रारंभ हुए ÷संकल्प से समाधान÷ अभियान के जिले में प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने द्वारा अधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान सुशासन, पारदर्शिता और जनहित में त्वरित समाधान की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य केन्द्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ प्रत्येक पात्र नागरिक तक समयबद्ध रूप से पहुंचाना है। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने कहा कि 12 जनवरी से प्रारंभ हो चुके इस अभियान को जिले में पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ संचालित किया जाए। उन्होंने सभी जिला, अनुविभागीय, विकासखंड एवं नगरीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि अभियान को केवल औपचारिकता न मानते हुए इसे जनसेवा के

संकल्प के रूप में क्रियान्वित करें और यह सुनिश्चित करें कि कोई भी पात्र हितग्राही योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में कलेक्टर ने अभियान की चरणबद्ध कार्ययोजना की समीक्षा करते हुए बताया कि संकल्प से समाधान अभियान 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक चार चरणों में संचालित किया जा रहा है। प्रथम चरण में ग्राम पंचायत एवं नगरीय निकायों के वार्ड स्तर पर गठित समितियों के माध्यम से आवेदन एवं शिकायतों का एकत्रीकरण किया जा रहा है। इसके लिए घर-घर संपर्क, शिविरों का आयोजन तथा वार्ड स्तरीय दलों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जाए। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि इस चरण में प्राप्त होने वाले प्रत्येक आवेदन को अनिवार्य रूप से सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर दर्ज किया जाए। कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने स्पष्ट किया कि अभियान की संपूर्ण कार्यवाही सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से ही संपादित की जा रही है, इसलिए सभी नोडल अधिकारी पोर्टल पर समय पर, सही एवं पूर्ण प्रविष्टि सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि आवेदन दर्ज करने में देरी, गलत प्रविष्टि या निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी की जवाबदेही तय की जाएगी। प्रथम चरण में प्राप्त आवेदनों की नियमित समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी। बैठक में द्वितीय चरण के संबंध में कलेक्टर ने बताया कि 16 फरवरी से 16 मार्च 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों में क्लस्टर स्तर पर तथा शहरी क्षेत्रों में जोन स्तर पर शिविर आयोजित कर प्रथम चरण में प्राप्त एवं शेष आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि क्लस्टर एवं जोन स्तर पर आयोजित शिविरों में संबंधित विभागों के अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें और यथासंभव मौके पर ही समस्याओं का समाधान कर हितलाभ वितरण किया जाए। कलेक्टर ने तृतीय चरण की जानकारी देते हुए कहा कि 16 मार्च से 26 मार्च 2026 तक विकासखंड एवं नगर स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनमें क्लस्टर एवं जोन स्तर पर अनिराकृत आवेदनों के साथ नवीन आवेदनों का भी निराकरण किया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि विकासखंड मुख्यालयों पर आयोजित शिविरों में वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए, जिससे नागरिकों को एक ही स्थान पर समाधान उपलब्ध हो सके। अभियान के चतुर्थ एवं अंतिम चरण पर चर्चा करते हुए कलेक्टर ने बताया कि 26 मार्च से 31 मार्च 2026 तक जिला स्तर पर शिविर आयोजित किए जाएंगे, जिनकी अध्यक्षता जिले के प्रभारी मंत्री द्वारा की जाएगी। इन शिविरों में शेष सभी अनिराकृत आवेदनों का निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को सम्मानपूर्वक हितलाभ वितरित किया जाएगा। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि 31 मार्च 2026 तक सभी आवेदनों का अंतिम निराकरण अनिवार्य रूप से किया जाना है। बैठक में कलेक्टर श्री बालागुरू के. ने यह भी निर्देश दिए कि शिविरों की तिथि, स्थान एवं समय की जानकारी आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए स्थानीय मीडिया, सोशल मीडिया एवं अन्य प्रचार माध्यमों का व्यापक उपयोग किया जाए, ताकि अधिक से अधिक नागरिक अभियान से जुड़ सकें। उन्होंने अधिकारियों से स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप नवाचार करने और जनहित में प्रभावी पहल करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि संकल्प से समाधान÷ अभियान शासन और जनता के बीच विश्वास को सुदृढ़ करने का माध्यम है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्माणाधीन गीता भवन का किया अवलोकन

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उज्जैन प्रवास के दौरान शासकीय माधव विज्ञान महाविद्यालय के समीप निर्माणाधीन गीता भवन का अवलोकन किया। जानकारी दी गई कि यह भवन जी प्लस टू निर्मित किया जाएगा, अप्रैल 2026 में इसके पूर्ण होना होने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसकी निर्माण एजेंसी पीडब्ल्यूडी पीआईयू है। गीता भवन की कुल क्षमता 1250 सीटर होगी। इसका निर्माण 5.11 एकड़ में लागत लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है।

इस दौरान विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, संजय अग्रवाल, संभागायुक्त आशीष सिंह, एडीजी उमेश जोगा, डीआईजी नवनीत भसीन, कलेक्टर रौशन कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा, एडीएम श्री अतेंद्र सिंह गुर्जर सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

सीएम 16 जनवरी को लाड़ली बहना योजना की 32वीं किश्त का बहनों के खातों मे करेंगे अंतरण

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गुरुवार, 16 जनवरी को माखन नगर (बाबई), जिला नर्मदापुरम में आयोजित लाड़ली बहनों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना अंतर्गत प्रदेश की बहनों के खातों में राशि का अंतरण करेंगे। प्रदेश की लगभग 1 करोड़ 25 लाख 31 हजार से अधिक पात्र बहनों के खातों में 1836 करोड़ रुपये से अधिक की राशि अंतरित की जायेगी। साथ ही 29 लाख बहनों को गैस सिलेंडर रीफिलिंग के लिए 90 करोड़ से अधिक राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया जायेगा। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 से की गई थी। योजना के अंतर्गत माह नवंबर 2025 से राशि में 250 रुपये की वृद्धि की गई है। अब पात्र हितग्राही महिलाओं को 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। योजना में जून 2023 से दिसंबर 2025 तक मासिक आर्थिक सहायता की 31 किश्तों का नियमित रूप से अंतरण किया जा चुका है। जनवरी 2026 में योजना की 32वीं किश्त का लाड़ली बहनों के खातों में अंतरण किया जायेगा। योजना अंतर्गत अब तक जून 2023 से दिसंबर 2025 की अवधि में कुल 48 हजार 632 करोड़ 70 लाख रुपये की राशि हितग्राही महिलाओं के खातों में अंतरित की जा चुकी है। जनवरी 2024 से दिसंबर 2025 के दौरान 38 हजार 635 करोड़ 89 लाख रुपये का अंतरण किया गया है। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से प्रदेश की महिलाओं के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और सम्मान सुनिश्चित किया गया है। आगामी समय में योजना की हितग्राही महिलाओं को विभिन्न रोजगार, स्वरोजगार एवं कौशल उन्नयन कार्यक्रमों से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे, जिससे वे आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बन सकें।

भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती के जन्मदिन पर होंगे अनेक सेवा कार्य

'एक साल बेमिसाल पर भाजपा जिलाध्यक्ष महंत भारती को बधाई

धार। भारतीय जनता पार्टी जिलाध्यक्ष पद पर महंत निलेश भारती के एक वर्ष पूर्ण होने पर एक साल बेमिसाल रहा। आपने अपने एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान कई नवाचार करते हुए संगठन की दशा व दिशा को एक नए स्वरूप में प्रस्तुत किया है। आपने एक वर्ष में संगठन के केन्द्रीय व प्रदेष नेतृत्व के निर्देशों का भलीभांति पालन करते हुए भाजपा सरकार के जनहितैषी कार्यों को जन-जन तक पहुंचाया व संगठन की कार्ययोजनाओं को जिले में लगातार प्रवास करते हुए मण्डल ही नहीं अपितु बूथ स्तर तक प्रत्यक्ष बैठकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। जिलाध्यक्ष महंत भारती राष्ट्रप्रथम व संगठन सर्वोपरि की भावना से निरंतर संगठन को मजबूती प्रदान करने का कार्य करते आ रहे है।

भाजपा जिला अध्यक्ष महंत निलेश भारती की गत वर्ष 16 जनवरी को जन्मदिन के दिन जिलाध्यक्ष पद पर नियुक्ति होने के बाद जिले में अनेक अभियान एवं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अपने जन्मदिन पर धार जिले में आना और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी वर्तमान भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ जेपी नड्डा जी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव जी का जिले में तीन से चार बार प्रवास कर लोकार्पण व भूमि पूजन में आना महंत निलेश भारती के लिए सौभाग्य की बात है महंत भारती कुशल संगठन के रूप में कार्य करते हुए प्रशासनिक अधिकारी एवं जिले के जन प्रतिनिधि व भाजपा कार्यकर्ताओं से सफल समन्वयक बनाकर कार्यक्रम को सफल बनाया। राष्ट्रीय कार्यक्रम मन की बात रेडियो कार्यक्रम प्रदेश में धार जिला तीन से चार बार अव्वल रहा।

भाजपा जिला अध्यक्ष के जन्मदिन16 जनवरी को तय कार्यक्रम- भाजपा जिला अध्यक्ष का 16 जनवरी को तय कार्यक्रम इस प्रकार हैं- सुबह 8 बजे रुद्राभिषेक सोमनाथ मठ सागौर 10 बजे रक्तदान शिविर सागौर 11 बजे गौ पूजन लक्ष्मी गौशाला जेतपुरा धार 11:30 पर कम्बल वितरण वृद्ध आश्रम धार दोपहर 12 बजे भोजन सेवा दीनदयाल रसोई केंद्र तथा 1 से 4 बजे तक भाजपा जिला कार्यालय धार में कार्यकर्ता द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन होगा तत्पश्चात शाम 5 बजे पीथमपुर में अनेक कार्यक्रम में शामिल होंगे। जानकारी भाजपा जिला मीडिया प्रभारी संजय शर्मा ने दी।